



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 29, 2008 /फाल्गुन 10, 1929

No. 75]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 29, 2008/PHALGUNA 10, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2008

सं. फा. 2(11)-बी (डी)/2008.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

बजट 2008-2009

वित्त मंत्री, पी. चिदम्बरम का भाषण

29 फरवरी, 2008

अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2008-09 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस सदन ने और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने मुझे सरकार की ओर से पांचों बजट प्रस्तुत करने का सम्मान प्रदान किया है—यह एक ऐसा अनूठा सम्मान है जो मेरे पूर्ववर्ती वित्त मंत्रियों में केवल डॉ. मनमोहन सिंह को प्राप्त था। उसके बाद आज मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

1. अर्थव्यवस्था : एक सिंहावलोकन

2. माननीय सदस्यगण, भारत के विकास की दास्तान, अब तक, एक दिलचस्प और प्रेरणादायी दास्तान रही है। जनवरी, 2005 से आरम्भ होकर, 31 दिसम्बर, 2007 तक लगातार 12 तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज हुई है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के पहले तीन वर्षों में, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.5 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत और 9.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप औसतन 8.8 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर हासिल हुई। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार मौजूदा वर्ष में भी वृद्धि दर 8.7 प्रतिशत होगी—यद्यपि मुझे विश्वास है कि हम 8.8 प्रतिशत का औसत बनाए रखेंगे। “सेवा” और “विनिर्माण” क्षेत्र इस वृद्धि के नियंता बने हुए हैं, जिनमें क्रमशः 10.7 प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

3. फिर भी, 2007-2008 विगत चार वर्षों में सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण रहा है। वर्ष के आरम्भ में, वैश्विक अर्थव्यवस्था का परिदृश्य अच्छा था। हमारी अपनी नीतियों तथा वैश्वीकरण के बलबूते हमारी अर्थव्यवस्था एक और वर्ष उच्च वृद्धि के मार्ग पर प्रशस्त थी : वास्तव में 2007-2008 के पूर्वार्ध में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई। लेकिन, अगस्त, 2007 से, विकसित देशों के वित्तीय बाजारों में बहुत अधिक उथल-पुथल दिखाई दी है जो अभी भी जारी है। विकासशील देशों के लिए इसके परिणाम भी अभी स्पष्ट नहीं हैं।

4. इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में निराशा हाथ लगी है। 2007-08 की पहली छमाही में अच्छी शुरुआत के बावजूद कृषि में सम्पूर्ण वर्ष की वृद्धि दर केवल 2.6 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है।

5. दूसरे मंदीकारक जोखिम भी रहे हैं। कच्चे तेल, विक्रय-वस्तुओं और खाद्यानों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अप्रैल 2007 से जनवरी 2008 तक तेजी से बढ़ी हैं। कच्चे तेल की स्थिति से यह सदन भली-भांति अवगत है। विक्रय-वस्तुओं में, लौह अवस्क, तांबा, सीसा, टिन, यूरिया आदि की कीमतें बढ़ी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूँ और चावल की कीमतें क्रमशः 88 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। ये सभी रुझान मुद्रास्फीतिकारी हैं, और घरेलू कीमतों, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव है। परिणामस्वरूप, खाद्य पदार्थों के आपूर्ति पक्ष का प्रबन्ध आगामी वर्ष में सर्वाधिक निर्णायक चुनौती रहेगा।

6. हमने यह भी देखा है कि पूंजी अन्तर्प्रवाह चालू खाता घाटे से बहुत अधिक है। यह मौद्रिक प्रबंधन के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है। इसका समाधान मध्यावधि में अर्थव्यवस्था की अवशोषक क्षमता बढ़ाने में निहित है। अल्पावधि में, यह हमारी जिम्मेदारी है कि इन प्रवाहों का अधिक सक्रियतापूर्वक प्रबन्धन करें। सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से स्थिति पर कड़ी नजर रखना और ऐसे अस्थाई उपाय करना जारी रखेगी जो मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के अनुरूप पूंजी प्रवाहों में संतुलन लाने के लिए आवश्यक होंगे।

7. मुद्रास्फीति को काबू में रखना हमारी नीति का एक अति महत्वपूर्ण पहलू है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, "मैं समझता हूँ कि हमारे देश में कोई भी सरकार विकास प्रक्रिया को बाधित किए बिना, उपयुक्त मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य के प्रति बेपरवाह नहीं रह सकती है।" नीति का इससे अधिक स्पष्ट कथन नहीं हो सकता है। तथापि, चूँकि पूरे विश्व में मंदीकारक जोखिम बढ़े हैं, अतः, हमें चौकस रहना चाहिए और मूल्य स्थिरता के साथ-साथ विकास का लक्ष्य हासिल करने की हमारी नीतियों में तीव्र समायोजन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।

8. सर्वप्रथम, मैं, कृषि की चर्चा करूंगा। इस समय, संक्षेप में और बाद में कुछ विस्तारपूर्वक। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि 2007-08 में खाद्यानों का कुल उत्पादन 219.32 मिलियन टन होगा और यह अब तक का एक रिकार्ड होगा। विशेष रूप से चावल का उत्पादन 94.08 मिलियन टन, मक्का का 16.78 मिलियन टन, सोयाबीन 9.45 मिलियन टन; कपास 23.38 मिलियन गांठे (प्रत्येक 170 किग्रा.) होने का अनुमान है और इन सभी का उत्पादन अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है। सरकार इस बात के प्रति सचेत है कि हालांकि बहुत कुछ किया गया है, और बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। पिछले बजट के बाद से, सरकार ने राष्ट्रीय कृषक नीति तैयार की है और घोषित की है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और 4,882 करोड़ रुपये के परिव्यय से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है। दोनों योजनाएं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाएंगी। हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होने के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। इस समय, मैं इस सदन के समक्ष कृषि क्षेत्र में की गई अनेक नई पहलों का उल्लेख करूंगा।

विकास गाथा : तीव्रतर और अधिक समावेशी

9. मैं, भारत की तरक्की की बात पर लौटता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी निरन्तर प्रगति पहले कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किए गए और अब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा आगे बढ़ाए गए आर्थिक सुधारों की नीति का नतीजा है।

10. यदि 1984 और 1991 भारत की अर्थव्यवस्था के इतिहास में निर्णायक मोड़ थे तो 2004 एक अन्य निर्णायक मोड़ था। इस विश्वास पर कि सतत वृद्धि बनाए रखी जा सकती है, सं.प्र.ग. सरकार ने राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम में विकास को अधिक समावेशी बनाने के अपने आशय की घोषणा की थी। महोदय, मैं, सम्मानपूर्वक, इस सदन से म्लितखित तथ्यों के आधार पर समावेशी विकास के संबंध में हमारे रिकार्ड का आकलन करने का आग्रह करता हूँ :

- इस सरकार के पहले दो वर्षों में कृषि ऋण दुगुना हो गया और मार्च, 2008 तक इसके 240,000 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंचना तय है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक उपाय साबित हुआ है।
- मध्याह्न भोजन योजना विश्व का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत 11.4 करोड़ बच्चे लाभान्वित होते हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिनमें 8,756 को 24 × 7 आधार पर चलाया गया है, को सुदृढ़ कर उन्नत स्वास्थ्य देखभाल को ग्रामीण भारत तक पहुंचाया गया है।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में आवासीय विद्यालयों में 182,000 बालिकाओं का दाखिला कराया गया है जिससे शिक्षा में लिंग भेद को पाटने में मदद मिली है।

भारत निर्माण

11. भारत निर्माण में 2007-08 में प्रभावशाली प्रगति हुई है। यह महात्वाकांक्षी कार्यक्रम अब 1,000 दिन से अधिक पुराना है। वर्तमान स्थिति के अनुसार वर्ष के प्रत्येक दिन 290 बस्तियों को पेयजल मुहैया कराया जाता है और 17 बस्तियों को हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ा गया है। वर्ष के प्रत्येक दिन 52 गांवों को टेलीफोन उपलब्ध कराए जाते हैं और 42 गांवों में बिजली पहुंचाई जाती है। वर्ष के प्रत्येक दिन, 4,113 ग्रामीण घरों का निर्माण पूरा किया जाता है।

12. अध्यक्ष महोदय, जैसे ही मैं यह भाषण लिखने बैठा था, एक पतली किताब मेरी नजर में आई, जिसका शीर्षक था "इंदिरा गांधी—सिलेक्टेड सेइंग्स"। चंद मिनटों में ही मुझे यह स्वर्णिम उक्ति मिल गई जिसे मैं उद्धृत करता हूँ "कोई व्यक्ति जितना अधिक करता है, जितना अधिक प्रयास करता है, उतना ही अधिक करने में वह सक्षम होता है।" अब तक मैंने जो कहा है, वह वास्तव में अधिक समावेशी विकास

का प्रमाण है, परन्तु यदि आप मुझे से पूछें कि क्या हम बेहतर कर सकते हैं तो मेरा उत्तर होगा “हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए।” वर्ष 2008-09 का बजट हमारे और अधिक दूरदर्शी होने तथा अधिक कार्य करने और बेहतर कार्य करने का अवसर है।

II. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना : निर्णायक दूसरा वर्ष

13. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मजबूत वृद्धि के साथ आरम्भ हुई है। इससे पूर्व कभी भी हमने कोई योजना पहले वर्ष में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से आरंभ नहीं की थी। सरकार योजना की सफलता के लिए योजना के दूसरे वर्ष को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानती है। वर्ष 2008-09 सुदृढ़ीकरण; मजबूत वित्तीय आधारों पर चल रहे कार्यक्रमों में मजबूती लाने; कार्यन्वयन की गहन मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय करने, तथा प्राप्त लक्ष्यों और उनकी गुणवत्ता के संदर्भ में परिणामों को मापने का वर्ष होना चाहिए। योजना दस्तावेज में यह परिकल्पित है कि दूसरे वर्ष में सकल बजटीय सहायता 228,725 करोड़ रुपये होगी। हमारे विचार में, यह राशि पर्याप्त नहीं होगी। अतः मैं सकल बजटीय सहायता को बढ़ाकर 243,386 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह 2007-08 में किए गए आबंटन की तुलना में 38,286 करोड़ रुपये अधिक होगी।

14. सकल बजटीय सहायता में से, केन्द्रीय आयोजना के लिए आबंटन 179,954 करोड़ रुपये होगा, जो 2007-08 की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक होगा।

15. मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ कि सभी जारी कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त निधियां प्रदान की जाएंगी।

16. भारत निर्माण के लिए, मैं 2007-08 में किए गए 24,603 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में, 31,280 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर क्षेत्र संघटक सहित) का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

शिक्षा : सर्व शिक्षा अभियान

17. शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे दो स्तम्भ हैं, जिन पर सामाजिक क्षेत्र में सुधारों की इमास्त टिकी हुई है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2007-08 के कुल आबंटन (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) 28,674 करोड़ रुपये की तुलना में 2008-09 में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर 34,400 करोड़ रुपये किया जाएगा।

18. इसमें से, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 13,100 करोड़ रुपये, मध्याह्न भोजन योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये, और माध्यमिक शिक्षा को 4,554 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

19. सर्व शिक्षा अभियान का केन्द्र बिन्दु प्राथमिक शिक्षा सुलभ बनाने और आधारभूत ढांचे के स्थान पर बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना होगा।

20. 6,000 उच्च उत्कृष्टता वाले मॉडल स्कूलों की स्थापना के लक्ष्य के साथ 2008-09 में मॉडल स्कूल कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मैं इस नई योजना के लिए 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

जवाहर नवोदय विद्यालय

21. जवाहर नवोदय विद्यालय उत्कृष्ट विद्यालय हैं। इन विद्यालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से, सरकार की योजना 20 जिलों में ऐसे नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने की है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की बहुलता होगी। मैं इस प्रयोजन हेतु 2008-09 में 130 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

22. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं की शिक्षा में समानता के मुद्दे का निराकरण करने के उद्देश्य से की गई थी। अब तक, 1,754 विद्यालय आरम्भ किए गए हैं और मैं शैक्षणिक रूप से पिछड़े खण्डों में 410 और विद्यालयों की स्थापना के लिए निधियां आवंटित करने (सर्व शिक्षा अभियान के भाग के रूप में) का प्रस्ताव करता हूँ। मैं बालिका विद्यालयों से सम्बद्ध नए छात्रावासों की स्थापना करने अथवा मौजूदा छात्रावासों का उन्नयन करने हेतु 80 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति

23. पिछले वर्ष, मैंने राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की थी ताकि छात्र आठवीं कक्षा से आगे और बारहवीं कक्षा तक शिक्षा जारी रख सकें। मैंने इस वायदे के साथ 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था कि अगले तीन वर्षों के लिए समान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना 2008-09 से क्रियान्वित की जाएगी और इसमें 100,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। अपना वायदा पूरा करते हुए, मैं 750 करोड़ रुपये आवंटित करता हूँ जिससे चार वर्ष में 3000 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि का निर्माण हो सकेगा।

नेहरू युवा केन्द्र

24. 123 जिलों में नेहरू युवा केन्द्र नहीं हैं। मैं इन जिलों में से प्रत्येक में एक केन्द्र की स्थापना के लिए 2008-09 में 10 करोड़ रुपये का आवंटन करने और पहले वर्ष में आवर्ती व्यय को वहन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मध्याह्न भोजन योजना

25. मध्याह्न भोजन योजना की प्रसुविधा शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3,479 खण्डों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए दी गई है। इस योजना का विस्तार अब देश में सभी विकास खण्डों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए किया जाएगा। इससे 2.5 करोड़ अतिरिक्त बच्चों को लाभ पहुंचेगा जिससे इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले बच्चों की कुल संख्या 13.9 करोड़ हो जाएगी।

उच्च शिक्षा संस्थान

26. ज्ञान शक्ति है। ज्ञान से ही 21वीं सदी में सफलता के द्वार खुलेंगे। भारत के पास ज्ञान से परिपूर्ण समाज बनने का अवसर है। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद शिलांग में एक भारतीय प्रबंध संस्थान; मोहाली, पुणे और कोलकाता में एक-एक आईआईएसईआर तथा काँचीपुरम में एक आईआईआईटी ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। सरकार अब तक कवर न किए गए राज्यों में प्रत्येक में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी। वर्ष 2008-09 में 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ हमारा इसे शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान में एक-एक आईआईटी, भोपाल और तिरुवनन्तपुरम में दो आईआईएसईआर तथा भोपाल और विजयवाड़ा में योजना और वास्तुकला के दो विद्यालय खोलने का हमारा प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री जी के वायदे के अनुसार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के ओर अधिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

27. मैं डक्कन स्नातकोत्तर कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, पुणे को 5 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव भी करता हूँ। यह भारत में आधुनिक शिक्षा के सर्वाधिक प्राचीन शैक्षणिक संस्थानों में है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

28. हमें अपने बच्चों को विज्ञान और अनुसंधान तथा विकास विषयों में कैरियर चुनने को प्रोत्साहित करना चाहिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उत्प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान वृत्ति में नवोन्मेष (इन्सपायर) नामक एक योजना प्रारम्भ करेगा जिसमें नौजवान शिक्षार्थियों (10-17 वर्ष) की छात्रवृत्तियों, सतत विज्ञान शिक्षा छात्रवृत्तियाँ (17-22 वर्ष) और अनुसंधान कैरियर (22 से 32 वर्ष) के लिए अवसरों को शामिल किया जाएगा। मैं ज्ञान आधारित समाज के निर्माण हेतु इस उत्प्रेरित योगदान के सम्बन्ध में वर्ष, 2008-09 के लिए 170 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

29. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा समय-समय पर की गई सिफारिशों पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है। कुछ सिफारिशों को ग्यारहवीं योजना में शामिल कर लिया गया है। सरकार ने सभी ज्ञान संस्थानों को इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल ब्राडबैंड नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ने की महत्वपूर्ण सिफारिश स्वीकार कर ली है। इससे संसाधनों में भागीदारी तथा संयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना के लिए सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 100 करोड़ रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

स्वास्थ्य

30. मैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए (पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित) 16,534 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ। इसमें वर्ष 2007-08 में किए गए आबंटन की तुलना में, 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

31. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) केन्द्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एक पूर्ण क्रियाशील, समुदाय आधारित, विकेन्द्रित स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली की स्थापना करना है। 462,000 सम्बद्ध सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) और लिक वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा वे कार्यरत हैं। 177,924 ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समितियाँ कार्यरत हैं। 323 जिला अस्पतालों का उन्नयन कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 2008-09 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य नियत किए गए हैं और मैं इस मिशन के लिए आबंटन को बढ़ाकर 12,050 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

एचआईवी/एड्स

32. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 993 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। अध्ययन में यह पाया गया है कि एचआईवी/एड्स की व्यापकता दर 0.9 प्रतिशत से घटकर 0.36 प्रतिशत रह गई है। यह कुछ हद तक सन्तोष का विषय है।

पोलियो

33. पोलियो को समाप्त करने का अभियान एक संशोधित रणनीति के तहत जारी है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उच्च जोखिम वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2008-09 में 1,042 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

34. वर्ष 2008-09 में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना है। प्रथम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बी.पी.एल. श्रेणी में आने वाले प्रत्येक ऐसे कामगार और उसके परिवार के लिए 30,000 रुपए के स्वास्थ्य कवर की व्यवस्था होगी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि अधिकांश राज्य इस योजना में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं और यह 1 अप्रैल, 2008 से दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान में प्रारम्भ की जाएगी। मैं वर्ष 2008-09 में केन्द्र के हिस्से के प्रीमियम के बतौर 205 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम

35. अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम वृद्ध जनों के लिए होगा। वर्ष 2008-09 में 400 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय से राष्ट्रीय वृद्धजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। अन्य उपायों के साथ-साथ हम ग्यारहवीं जंचवर्षीय योजना के दौरान दो राष्ट्रीय वृद्धजन देखरेख संस्थान, आठ क्षेत्रीय केन्द्र और प्रत्येक राज्य में एक मेडिकल कॉलेज/तृतीय (टरशियरी) अस्पताल में एक जरा चिकित्सा देखभाल विभाग स्थापित करेंगे।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

36. एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के सार्वजनीकरण का कार्य जारी है। दिसम्बर, 2007 के अन्त में 5,959 आईसीडीएस परियोजनाएं और 932,000 आंगनवाड़ी केन्द्र और छोटे आंगनवाड़ी केन्द्र कार्यरत थे। लाभार्थियों की अभिवृद्धित संख्या बढ़ कर 629 लाख बच्चे और 132 लाख गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं हो गईं। मैं इस योजना के लिए आबंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 5,293 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2008-09 में 6,300 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।

37. मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मेहनताना 1,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी सहायकों का मेहनताना 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। 18 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगी।

अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम

38. जैसाकि माननीय सदस्यों को पता है, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के आठ अग्रगामी कार्यक्रम हैं। मैंने अभी तक शिक्षा क्षेत्र के दो (एसएसए और एमएमएस) और स्वास्थ्य क्षेत्र के दो (एनआरएचएम और आईसीडीएस) कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला है। अब मैं चार अन्य अग्रगामी कार्यक्रमों पर प्रस्तावित आवंटन का उल्लेख करूंगा :

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरजीएस) को भारत के सभी 596 ग्रामीण जिलों में प्रारम्भ किया जाएगा। प्रारम्भ में, हम इसके लिए 16,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएंगे। इस पर किसी के दिमाग में यह आशंका नहीं होनी चाहिए ज्यों मांग में बढ़ोतरी होगी, रोजगार की वैध गारंटी की पूर्ति हेतु और अधिक धन उपलब्ध कराया जाएगा।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी आधारभूत संरचना में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह मिशन शहरी शासन तथा नगरों से संबंधित कानूनों में सुधार लाने में भी सफल हुआ है। मैं आबंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 5,482 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2008-09 में 6,866 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ।
- राजीव गांधी पेयजल मिशन का उद्देश्य कवर न की गयी बस्तियों और छूट गयी बस्तियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करना और स्वच्छ पेयजल से जुड़े गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करना है। मैं आबंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 6,500 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़ाकर 2008-09 में 7,300 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ।
- अभी तक इस मिशन के अन्तर्गत जल की कमी वाले स्थानों के स्कूली बच्चों के लिए पृथक संघटक नहीं हैं। हमारे बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। इसलिए, मैं, मिशन को पृथक उपशीर्ष के अंतर्गत निधियां आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि जल की कमी वाली बस्तियों में प्रत्येक स्कूल को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एकल प्रणाली संस्थापित की जाए। प्रत्येक प्रणाली की लागत, उसकी प्रौद्योगिकी तथा डिजाइन को देखते हुए 15,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच होने का अनुमान है। चूंकि चार वर्षों हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, अतः मैं, वर्ष 2008-09 में 200 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।
- पूर्ण स्वच्छता अभियान में लोगों की आदतों तथा मनोवृत्तियों में पूरी तरह बदलाव लाना निहित है, और यह एक अनवरत प्रक्रिया है। मैं, वर्ष 2008-09 में 1,200 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अपक्षारीकरण संयंत्र

39. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने जुलाई 2004 में चेन्नई के निकट खारापन दूर करने का एक संयंत्र लगाने के लिए अपने समर्थन की घोषणा की थी। अब तमिलनाडु सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी के तहत एक संयंत्र लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। चूंकि इस प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु जांच की जाएगी, इसलिए मैं, वर्ष 2008-09 में इस परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता देने का प्रस्ताव करता हूँ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

40. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा और इसके आबंटन में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) को 1,455 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। इस राशि सहित, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के आबंटन के साथ डोनर के संबंध में कुल बजट आबंटन, वर्ष 2007-08 में किए गए 14,365 करोड़ रुपये से बढ़कर 2008-09 में 16,447 करोड़ रुपये हो जाएगा।

41. पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश तथा सीमावर्ती क्षेत्र विशेष समस्याओं का सामना करते हैं और जिनको सामान्य तरीकों से अथवा सामान्य स्कीमों के माध्यम से नहीं निपटया जा सकता। इसलिए, सरकार का इन क्षेत्रों की त्वरित आवश्यकताओं की पहचान करने और उन्हें विशेष व्यवस्था के तहत पूरा करने का प्रस्ताव है। इस प्रक्रिया पर कार्यवाही करने हेतु मैं इस उद्देश्य हेतु समर्पित निधि में 500 करोड़ रुपये की राशि रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक

42. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाता रहेगा।

विकास और वित्त निगम

43. कतिपय लाभ वंचित वर्गों के लिए विकास और वित्त निगमों की स्थापना की गयी है। मैं, इन निगमों के संबंध में निम्न प्रकार से अतिरिक्त इक्विटी सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ :

	करोड़ रुपए
1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम	75.00
2. कमजोर वर्गों के लिए तीन राष्ट्रीय वित्त और विकास निगम जिनमें शामिल हैं :	106.50
(i) सफाई कर्मचारी	
(ii) अनुसूचित जाति	
(iii) पिछड़ा वर्ग	
3. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	50.00
4. राष्ट्रीय विकलांग विकास निगम	9.00

छात्रवृत्तियां

44. पिछले बजटों में, मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए कई मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की घोषणा की थी।

सभी कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जा चुका है। ये सभी कार्यक्रम वर्ष 2008-09 में पर्याप्त निधियों के साथ जारी रहेंगे :

अनुसूचित जाति	804 करोड़ रुपए
अनुसूचित जनजाति	195 करोड़ रुपए
अन्य पिछड़ा वर्ग	164 करोड़ रुपए
अल्पसंख्यक (मैट्रिकोत्तर)	100 करोड़ रुपए

45. मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कार्यक्रम हेतु वर्ष 2008-09 में 75 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, यह कार्यक्रम एम. फिल. तथा पी. एच.डी. पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

46. वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ की गयी प्रक्रिया के अनुसरण में, मैंने बजट दस्तावेज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी योजना का विवरण शामिल किया है। मैंने अनन्य रूप से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों हेतु 3,966 करोड़ रुपए और 18,983 करोड़ रुपए, उन स्कीमों हेतु व्यवस्था की है, जहां कम से कम 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए नियत है।

अल्पसंख्यक

47. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के आवंटन को वर्ष 2007-08 में किए गए 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 1,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार ने न्यायमूर्ति राजेन्द्र सच्चर समिति रिपोर्ट पर तेजी से अमल करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2007-08 में घोषित स्कीमों के अलावा, वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित स्कीमों/उपायों को कार्यान्वित करना प्रस्तावित है :

- 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से प्रत्येक जिले में एक बहु क्षेत्रीय विकास योजना तैयार की जाएगी। वर्ष 2008-09 में आवंटन 540 करोड़ रुपए होगा;
- 80 करोड़ रुपए के आवंटन से मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना;

- मदरसा शिक्षा को आधुनिकीकरण योजना कार्यान्वित की जाएगी, और वर्ष 2008-09 में इसके लिए 45.45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया;
- पर्याप्त अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले जिलों में दिसम्बर, 2007 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 256 शाखाएं खोली गयीं। मार्च, 2008 तक 288 शाखाएं और 2008-09 में कई और शाखाएं खोली जाएंगी;
- इस वर्ष प्रारम्भ की गयी कार्रवाई को जारी रखते हुए, अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध अधिक अभ्यर्थियों को केन्द्रीय-अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती किया जाएगा।

48. मैं, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की कारपस निधि को बढ़ाने हेतु 60 कोड़ रुपए का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

महिला और बाल

49. मैं स्वीकार करता हूं कि नीति निर्माता अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि अभी जनसंख्या महिलाओं की है और वे सभी कार्यक्रमों तथा स्कीमों में बराबर भागीदारी पाने तथा समान मत व्यक्त करने की पात्र हैं। लिंग आधारित बजटीय व्यवस्था (बैंडर बजटिंग) ने व्यापक स्वीकृति और विश्वसनीयता प्राप्त की है। चार और मंत्रालयों/विभागों ने बैंडर बजटिंग प्रकोष्ठों की स्थापना की है और इनकी कुल संख्या 54 हो गयी है। माननीय सदस्य बजट दस्तावेज में एक विवरण देखेंगे जिसमें 27 मंत्रालयों/विभागों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों की 33 अनुदान-मार्गे शामिल हैं। इस विवरण के अनुसार, 100 प्रतिशत महिला विशिष्ट योजनाओं के लिए 11,460 करोड़ रुपए और कम से कम 30 प्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 16,202 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

50. हम इस वर्ष एक अन्य पहल करेंगे। बजट दस्तावेज में बाल सम्बद्ध योजनाओं का एक विवरण शामिल किया गया है और माननीय सदस्यों को यह जानकारी प्रसन्नता होगी कि बाल संबंधी इन योजनाओं पर कुल परिच्यय 33,434 करोड़ रुपए होगा।

51. मैं महिला और बाल विकास मंत्रालय को वर्ष 2008-09 में 7,200 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। यह वर्ष 2007-08 में किए गए आवंटनों की तुलना में 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।

स्व-सहायता समूह

52. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जनश्री बीमा योजना संचालित कर रहा है और यह 44 श्रेणी के लोगों को जीवन तथा स्थायी विकलांगता का कवर प्रदान करता है। इनमें से एक श्रेणी स्व-सहायता समूहों की है, लेकिन अभी तक केवल 35,000 स्व-सहायता समूहों को शामिल किया गया है। इस तथ्य पर विचार करते हुए, कि 30 लाख से अधिक स्व-सहायता समूह बैंकों की ऋण व्यवस्था से जुड़े हैं, मैं इस श्रेणी पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं, एलआईसी से यह प्रस्ताव करता हूं कि वह इस स्कीम का शीघ्रता से विस्तार करें और ऋण के लिए बैंकों से जुड़े सभी महिला स्व-सहायता समूहों को शामिल करें। चूंकि प्रीमियम का आधा हिस्सा सामाजिक सुरक्षा निधि के माध्यम से सब्सिडी रूप में प्राप्त है, इसलिए मैं, इस कारपस निधि को 500 करोड़ रुपए का अंशदान इस आवासन के साथ प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं कि जैसे ही इस स्कीम का विस्तार होगा, इसे वार्षिक अंशदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ यह स्कीम महिलाओं के संबंध में उन्हें जीवन तथा स्वास्थ्य कवर की व्यवस्था करते हुए एक नई प्रणाली का सूत्रपात करेगी।

सकल बजटीय सहायता का सम्पूर्ण

53. माननीय सदस्य देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों और योजनाओं के लिए आवंटन भरपूर हैं। मैं निःसंकोच यह स्वीकार करता हूं कि इस दिशा में और अधिक आवंटन किया जा सकता है तथा यह किया भी जाएगा। हालांकि इसके लिए लिए एक शर्त है और वह है कार्य निष्पादन की। मैंने पिछले बजट में एक आयोजना "ख" की घोषणा की थी और उसके लिए मैं दो पूरक मांगों के माध्यम से 8,365 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आयोजना निधियों की व्यवस्था कर सका और तीसरी के माध्यम से भी शीघ्र की जाएगी। इस समस्या की जड़ कार्यान्वयन में निहित है और कार्यान्वयन अधिकांशतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस वर्ष भी मेरा इरादा 10,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का है जिसे आयोजना पूंजीगत व्यय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यह धनराशि-आयोजना "ख" के अंतर्गत-केन्द्र सरकार के उन मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों को उपलब्ध होगी जो विभिन्न आयोजना/स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित भौतिक और गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

कृषि

54. मैं अब पुनः कृषि विषय पर आता हूं।

55. मैंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पहले ही उल्लेख किया है।

कृषि ऋण

56. कुछ कमियों के होते हुए भी, कृषि ऋण की वृद्धि प्रभावशाली रही है और इसके लिए मैं अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को धन्यवाद देता हूँ। उनके बीच किसी एक वर्ष के दौरान संवितरित कृषि ऋण लगभग 75-79 प्रतिशत बैठता है। हम 2007-08 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पार कर जाएंगे। मैं, 2008-09 के लिए 2,80,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य नियत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

57. अल्पावधिक फसल ऋण 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संवितरित किए जाते रहेंगे और मैं 2008-09 में ब्याज सहायता के लिए 1,600 करोड़ रुपये का प्रारंभिक प्रावधान कर रहा हूँ।

कृषि में निवेश

58. कृषि को अन्य बातों के साथ, जो रुग्ण बनाती है वह है घटता निवेश। यद्यपि, अब व्यापक परिवर्तन दिखाई देता है। कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में समग्र पूंजी निर्माण 2003-04 में 10.2 प्रतिशत के निम्न स्तर से सुधरकर 2006-07 में 12.5 प्रतिशत हो गया है। हालाँकि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4 प्रतिशत के वृद्धि दर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने की जरूरत है।

जल संसाधन

59. सरकार त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम (एआईबीपी) और वर्षापोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा जल संसाधनों के प्रबंधन और संवर्धन में भारी निवेश कर रही है। एआईबीपी के अंतर्गत, इस वित्त वर्ष में 24 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएँ तथा 753 छोटी सिंचाई योजनाएँ पूरी कर ली जाएंगी इससे 500,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हो सकेगी। 2007-08 के लिए 3,580 करोड़ रुपये के अनुदान घटक के साथ परिव्यय 11,000 करोड़ रुपये था। इन्हें 2008-09 में बढ़ाया जा रहा है और 5,550 करोड़ रुपये के अनुदान घटक के साथ अनुमानित परिव्यय 20,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।

60. वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है और इसे 348 करोड़ रुपये के आबंटन से 2008-09 में क्रियान्वित किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी तक जल संभरण विकास योजनाओं के लाभार्थी नहीं रहे हैं।

61. जनवरी, 2006 में शुरू की गई सूक्ष्म सिंचाई संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत दो साल के भीतर 548,000 हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप और फव्वारा सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। मैं अतिरिक्त 400,000 हेक्टेयर को शामिल करने के लक्ष्य के साथ 2008-09 में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

62. जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और बहाली की परियोजना के अंतर्गत, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों ने विश्व बैंक के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये तीन करार 738 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि के हैं जो 900,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र को लाभ पहुंचाएंगे। मुझे विश्वास है कि विश्व बैंक और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व कुछ अन्य राज्यों की सरकारों के बीच शीघ्र ऐसे करार हस्ताक्षरित होंगे।

सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम

63. जबकि ये चालू कार्यक्रम कृषि में निवेश का स्तर बढ़ाएंगे, और मैं सोचता हूँ कि हमें अपेक्षाकृत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की जरूरत है। सरकार का मत है कि सिंचाई परियोजनाओं में भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता है। हाल में, सरकार ने 14 परियोजनाएँ अनुमोदित की हैं जो राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में कतिपय मानदंड पूरे करती हैं और ग्यारहवीं योजना की अवधि के दौरान उनमें से अकेली तीन परियोजनाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इस चुनौती के महत्व को स्वीकार करते हुए, मैं केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये के आरंभिक अंशदान से सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम (आईडब्ल्यूआरएफसी) के गठन का प्रस्ताव करता हूँ। राज्य सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इसकी इक्विटी में अंशदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हमारा अभिप्राय बहुत अधिक संसाधन जुटाने का है जिनकी आवश्यकता दीर्घकाल तक चलने वाली बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना के निधिपोषण के लिए होगी। मुझे आशा है कि मैं 31 मार्च, 2008 से पहले इस निगम को एक कंपनी के रूप में निगमित कर सकूंगा।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

64. राष्ट्रीय बागवानी मिशन अब 18 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों के 340 जिलों को कवर करता है। 276,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बागवानी फसलों के अंतर्गत लाया गया है और 56,000 हेक्टेयर के पुराने बागानों का पुनरुद्धार किया गया। नारियल, काजू और काली मिर्च जैसी फसलों के पुनरुज्जीवन पर विशेष बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 2008-09 में 1,100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

65. ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रति प्रयोगशाला 30 लाख रुपये की सरकारी सहायता से सरकारी और निजी क्षेत्र में 500 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, मैं, मार्च 2009 से पहले देश के 250 जिलों में एक पूर्णतया सज्जित चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था करने के लिए कृषि मंत्रालय को 75 करोड़ रुपये के एकमुश्त आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

बागानी फसलें

66. पुनरोपण और नवीकरण के लिए पिछले वर्ष गठित विशेष प्रयोजन चाय निधि को 2008-09 में 40 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं इलायची (10.68 करोड़ रुपये), रबड़ (19.41 करोड़ रुपये) और कॉफी (18 करोड़ रुपये) जैसी अन्य बागानी फसलों को ऐसी ही सहायता देने के लिए निधियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ। चाय, रबड़, तंबाकू, मिर्च, अदरक, हल्दी, काली मिर्च और इलायची के लिए फसल बीमा योजना अगले साल शुरू की जाएगी।

67. बागान क्षेत्र से संबद्ध मामलों पर अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं विकास अध्ययन केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम को एक बारगी 5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। चाय अनुसंधान एसोसिएशन का जोरहाट स्थित टोक्लाई एक्सपेरीमेंटल स्टेशन वर्ष 2010 में अपनी शताब्दी मनाएगा। यह अपनी सुविधाओं के उन्नयन की प्रक्रिया में है और अपनी गतिविधियों का विस्तार अन्य पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तरी बंगाल और दार्जिलिंग में कर रहा है। मैं चाय अनुसंधान एसोसिएशन को 20 करोड़ रुपये का विशेष शताब्दी अनुदान प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

68. हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पादप प्रशिक्षण संस्थान को 29.4 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से एक स्वायत्त राष्ट्रीय स्वस्थ पदार्थ प्रबंधन संस्थान में बदला जाएगा और उन्नयन किया जाएगा।

फसल बीमा

69. वैकल्पिक फसल बीमा योजना किसानों को स्वीकार्य और बीमाकर्ताओं के लिए व्यवहार्य है, जिसपर निर्णय के लक्षित रहते राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को इसके वर्तमान स्वरूप में खरीफ और रबी 2008-09 में जारी रखा जाएगा। मैं इस योजना के लिए 644 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ।

70. इसके अतिरिक्त, मौसम आधारित फसल बीमा योजना 5 राज्यों के चुनिंदा क्षेत्रों में एक प्रयोगिक योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। मेरा इरादा 2008-09 में इस प्रयोजनार्थ 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने का है।

71. सरकार किसानों को सब्सिडीयुक्त कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराती रहेगी। सरकार पोषक आधारित सब्सिडी व्यवस्था और सब्सिडी देने के वैकल्पिक तरीके अपनाने के प्रस्तावों की जांच कर रही है।

सहकारी ऋण संरचना

72. अल्पाधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन संबंधी प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट 17 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है। अब तक, केन्द्र सरकार द्वारा चार राज्यों को 1,185 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें दीर्घाधिक सहकारी ऋण ढांचे के पुनरुज्जीवन संबंधी प्रोफेसर वैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने के पैकेज की सहमति संबंधी एक समझौते पर पहुंच गए हैं। इस पैकेज की लागत 3,074 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा कुल भार का 2.642 करोड़ रुपये अथवा 86 प्रतिशत होगा।

ऋण माफी और ऋण राहत

73. महोदय मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे योजनाएं और उपाय जो मैंने ऊपर सूचीबद्ध किए हैं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। एक प्रश्न अभी भी प्रासंगिक है कि हमें किसानों की ऋण-ग्रस्तता के बारे में क्या करना चाहिए। माननीय सदस्यों को याद होगा कि सरकार ने कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी समिति ने अनेक सिफारिशों की थीं परन्तु कृषि ऋणों की माफी की सिफारिश नहीं की। लेकिन सरकार को इस समस्या की भयावहता की जानकारी है और वह किसान समुदाय विशेषतया छोटे और सीमांत किसानों की मुश्किलों के प्रति सचेत है। ऋण माफी के पक्ष और विपक्ष में ध्यानपूर्वक विचार और संसाधन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत की एक योजना इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ :

((i) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा 31 मार्च, 2007 तक संवितरित और 31 दिसंबर, 2007 को अतिदेय सभी कृषि ऋणों के इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा।

(ii) सीमांत किसानों (1 हेक्टेयर तक जोत वाले) और छोटे किसानों (1-2 हेक्टेयर) के लिए उन सभी ऋणों की पूर्ण माफी होगी जो 31 दिसंबर, 2007 को अतिदेय हो गए थे और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे। अन्य किसानों के संबंध में सभी ऋणों के लिए एक बारगी निपटान योजना होगी जो 31 दिसंबर, 2007 को अतिदेय हो गए और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे। एक बारगी निपटान के अंतर्गत 75 प्रतिशत शेष के भुगतान के एवज में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

- (iii) बैंकों द्वारा विशेष पैकेजों के माध्यम से 2004 और 2006 में कृषि ऋण पुनर्संचित और पुनर्निर्धारित किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में ये पुनर्संचित ऋण और अन्य पुनर्संचित ऋण भी या तो माफी के अथवा इसी पद्धति पर एक बारगी निपटान के पात्र होंगे।
- (iv) ऋण माफी और ऋण राहत योजनाएं 30 जून, 2008 तक पूरी कर ली जाएंगी। ऋण माफी दिए जाने अथवा एक बारगी निपटान के अंतर्गत ऋण राहत के समझौते पर हस्ताक्षर होने पर, किसान सामान्य नियमों के अनुसार बैंकों से नए कृषि ऋण लेने के हकदार होंगे।
- (v) सरकार का अनुमान है कि लगभग 3 करोड़ रुपए छोटे और सीमांत किसानों तथा लगभग 1 करोड़ अन्य किसानों को इस योजना से लाभ प्राप्त होगा। माफ किए जा रहे अतिदेय ऋणों का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपये अनुमानित है और एकबारगी निपटान में 10,000 करोड़ रुपये के अतिदेय ऋणों को राहत मिलने का अनुमान है।

मैं माननीय सदस्यों के साथ-साथ भारत की जनता से अपील करता हूँ कि वे इस योजना को अपना पूर्ण समर्थन दें तथा इस महत्वपूर्ण निर्णय को कार्यान्वित करने में सरकार को सहयोग दें।

IV. निवेश, अवसंरचना उद्योग और व्यापार

74. वर्ष 2005-06 से, निवेश में सुस्पष्ट धूम रही है। दो संकेतक यह कहानी बताते हैं। 2003-04 में बचत दर और निवेश दर क्रमशः 29.8 प्रतिशत और 28.2 प्रतिशत थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार, 2007-08 के अंत तक ये दरें क्रमशः 35.6 प्रतिशत और 36.3 प्रतिशत होंगी। यह प्रवृत्ति विदेशी निवेश की दिशा में भी परिलक्षित हुई है। अप्रैल-दिसम्बर, 2007-08 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 12.7 बिलियन अमरीकी डॉलर और विदेशी संस्थागत निवेश 18 बिलियन अमरीकी डॉलर राशि के रहे हैं। हमारी नीति घरेलू और विदेशी, निजी और सरकारी निवेश के सभी स्रोतों को प्रोत्साहित करने की है।

75. 2008-09 में, सरकार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में इक्विटी सहायता के रूप में 16,436 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,003 करोड़ रुपये उपलब्ध करागी। आज 44 सीपीएसई सूचीबद्ध हैं। सरकार की नीति है कि अधिक सीपीएसई को सूचीबद्ध किया जाए ताकि उनकी वास्तविक क्षमता प्रकट की जा सके और कारपोरेट अभिशासन में सुधार किया जा सके।

ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि

76. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) ग्रामीण अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए बैंक निधियों को सरणीकृत करने का मुख्य साधन है और यह राज्य सरकारों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। इसलिए मैं, 2008-09 में इस विकास निधि की संग्रह निधि बढ़ाकर 14,000 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, 4,000 करोड़ रुपये की निधि से आरआईडीएफ-XIV के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए अगल विंडो संचालित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

विनिर्माण क्षेत्र

77. छः महत्वपूर्ण अवसंरचना उद्योगों के उत्पादन के सूचकांक तथा अप्रैल-दिसम्बर 2007-08 अवधि के लिए समग्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुछ मंदी हुई है। यह गिरावट उपभोक्ता वस्तुओं, खासकर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के मामले में कुछ तीव्र रही है। आशा की किरण यह है कि पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि 20.2 प्रतिशत पर अभी भी बहुत ऊंची है जो यह दर्शा रही है कि उद्योग में भारी पूंजी निवेश हो रहे हैं और भविष्य के बारे में उनका दृष्टिकोण सकारात्मक है। विनिर्माण उद्योग, जो औसत से अधिक मंदी से बड़े हैं, में परिधान, कागज और परिवहन उपस्कर सहित खाद्य उत्पाद, सूती वस्त्र, उत्पाद शामिल हैं। इस मंदी के कारणों में ब्याज दरों में वृद्धि और रुपये की मूल्य वृद्धि हैं। मौद्रिक नीति समंजन की सीमाएं हैं, खासकर जब मूल्य स्थिर रखने की जरूरत हो। यद्यपि, राजकोषीय दिशा में कुछ उपाय किए जा सकते हैं और मैं औद्योगिक वृद्धि बढ़ाने के लिए अब सदन के समक्ष कुछ प्रस्ताव रख रहा हूँ। हमारा लक्ष्य विनिर्माण वृद्धि दर को दो अंकों में ले जाने का है। इसके लिए कोयला और बिजली क्षेत्रों के साथ-साथ सीमेंट और इस्पात क्षेत्रों में कम विक्रेताओं और कुछ ही फर्मों द्वारा नियंत्रण की विरोधाभासी स्थिति की प्रवृत्तियों में और सुधारों की जरूरत पड़ेगी।

विद्युत

78. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य 78,577 मेगावाट क्षमता है। यह पिछली तीन योजनाओं में जुड़ी कुल क्षमता से अधिक है। मार्च 2008 के अंत तक, हम किसी योजना अवधि में पहला सबसे अच्छा साल चिन्हित करते हुए लगभग 10,000 मेगावाट की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दोहरे प्रयास करेगी कि ग्यारहवीं योजना का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए।

79. चौथी अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी), तिलैया का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बोली अवस्था के लिए पांच और यूएमपीपी लाने की संभावना है, बशर्ते कि राज्य अपेक्षित सहायता प्रदान करें। मैं उनसे ऐसा करने का आग्रह करता हूँ।

80. सरकार ने 28,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जारी रखने का अनुमोदन कर दिया है। मैं योजना के लिए 2008-09 में 5,500 करोड़ रुपए (एनईआर सहित) आर्बिट्र करे का प्रस्ताव रखता हूँ।

81. मैं त्वरित विद्युत विकास और सुधार परियोजना के लिए 2008-09 में 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखता हूँ, तथापि, पारेषण और वितरण खस्ता हाल में है, जो इस सेक्टर के लिए बाधक है। पारेषण और वितरण में भारी निवेश करने की आवश्यकता है परन्तु यह मूलभूत सुधारों से सम्बद्ध होना चाहिए। अतः मैं पारेषण और वितरण सुधार के लिए राष्ट्रीय निधि का सृजन करने का प्रस्ताव रखता हूँ। योजना का ब्यौरा जल्द ही तैयार किया जाएगा और इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

सड़क

82. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के सभी चरणों में प्रगति जारी है। स्वर्णिम चतुर्भुज के पूरा होने की दर 96.48 प्रतिशत और उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम मार्ग परियोजना की दर 23.36 प्रतिशत है। एसएआरडीपी-एनई, कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2007-08 में 180 कि.मी. सड़क पूरी की गई है और 2008-09 के लिए 300 कि.मी. सड़क निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं एनएचडीपी के लिए आवंटन, 2007-08 में किए गए 10,867 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 12,966 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

तेल और गैस

83. नई खोज लाइसेंसिंग नीति के तहत बोली का 7वां दौर दिसम्बर, 2007 में प्रारंभ किया गया और 57 अन्वेषण ब्लॉकों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं। यह अनुमान है कि अन्वेषण और खोज के लिए यह दौर 3.5 बिलियन अमरीकी डालर से 8 बिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश आकर्षित करेगा।

कोयला

84. सरकारी और निजी क्षेत्र की कम्पनियों को 13,842 मिलियन टन आरक्षित भण्डार वाले 53 कोयला ब्लॉक अप्रैल-जनवरी 2007-08 के दौरान आर्बिट्र किए गए हैं। अक्टूबर 2007 में एक नई कोयला वितरण नीति अधिसूचित की गई थी। एक कोयला विनियामक नियुक्त किया जाएगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

85. सरकार की दूरदर्शी नीति से सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में वृद्धि हो रही है। मैं, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आवंटन को 2007-08 में किए गए 1,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 1,680 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में 100,000 ब्रॉड बैंड इंटरनेट आधारित सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए एक योजना तथा केन्द्रीय सहायता से राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान) स्थापित करने की एक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य आंकड़ा केन्द्रों के लिए नई योजना भी अनुमोदित हो गई है। मैं सामान्य सेवा केन्द्रों के लिए 75 करोड़ रुपए, स्वान के लिए 450 करोड़ रुपए और राज्य व्यापी केन्द्रों के लिए 275 करोड़ रुपए के प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वस्त्र

86. कपड़ा मंत्रालय की दो मुख्य योजनाएं—समेकित वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ)—ग्यारहवीं योजना अवधि में जारी रहेंगी। सभी 30 समेकित वस्त्र पार्कों का अनुमोदन किया गया है और चार पार्कों के 20 एककों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। मैं, 2008-09 में एसआईटीपी के लिए 425 करोड़ रुपए के प्रावधान को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। टीयूएफ के प्रावधान को वर्तमान वर्ष में किए गए 911 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2008-09 में 1,090 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

87. हथकरघा सेक्टर के विकास के लिए सामूहिक दृष्टिकोण में त्वरित प्रगति हुई है। 250 समूहों का विकास किया जा रहा है। 443 यार्न बैंक स्थापित किए गए हैं। मार्च 2008 तक, 17 लाख से अधिक बुनकर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा। मैं, इसके लिए आवंटन बढ़ाकर 2008-09 में 340 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

88. अवसंरचना और उत्पादन दोनों में वृद्धि करने के लिए, बड़े समूहों के रूप में छह केन्द्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है। वाराणसी और सिबसागर में हथकरघा, भिवंडी और इरोड में पावरलूम और नरसापुर एवं मुरादाबाद में हस्तशिल्प का विकास कार्य शुरू किया जाएगा। प्रत्येक मेगा समूह के लिए लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी। मैं, 2008-09 में, 100 करोड़ रुपए के आर्थिक प्रावधान से यह प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ।

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग

89. माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यमों को सरकार से सहायता मिलती रहेगी। मैं, इस सेक्टर के बारे में कुछ गलत धारणाओं को दूर करना चाहता हूँ। 2006-07 को समाप्त चार वर्षों जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, में पंजीकृत यूनिटों की संख्या, अपंजीकृत यूनिटों की संख्या, उत्पादन, रोजगार और निर्यातों में लगातार वृद्धि हुई है। इस सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक (सिडबी) में जोखिम पूंजी निधि के सृजन करने का प्रस्ताव करता हूँ। 31 जनवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, सिडबी के साथ ऋण गारंटी न्यास ने 2,479 करोड़ रुपये की राशि के लिए 89,129 यूनिटों को गारंटी प्रदान की थी। सिडबी गारंटी शुल्क 1.5 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करेगा और 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वार्षिक सेवा शुल्क 0.75 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करेगा।

विदेश व्यापार

90. रुपये के मूल्य में वृद्धि होने के कारण, पण्य निर्यात कुछ दबाव में है और यह 160 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य से कम हो सकता है। यद्यपि अप्रैल-दिसम्बर, 2007-08 के दौरान वृद्धि दर 21.8 प्रतिशत पर मजबूत थी। निर्यातकों को तीन किस्तों में लगभग 8,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई। मैं यह कह सकता हूँ कि बाजार स्थिरीकरण योजना बाँडों (एमएसएस) के माध्यम से, व्याज निष्क्रियकरण लागत पूरे वर्ष के लिए 8,351 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। यह निर्यात क्षेत्र के लिए सब्सिडी के रूप में है। सरकार निर्यात क्षेत्र की आवश्यकताओं के प्रति सचेत है और यह परिस्थिति के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती रहेगी।

V. वित्तीय सेक्टर

91. सावधानीपूर्वक और अंशांकित वित्तीय क्षेत्र खोलने की सरकार की नीति कारगर सिद्ध हुई है। हम, समुचित कदम उठाते रहेंगे।

92. वित्तीय समावेशन संबंधी समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। आरंभ में, मैं ये दो सिफारिशें स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी प्रत्येक ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखा में प्रति वर्ष कम से कम 250 ग्रामीण परिवारों का खाता खोलने का सुझाव देना; और
- व्यष्टियों यथा सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को व्यवसाय सुविधाकारक या व्यापार-सह-सम्बन्धी अथवा ऋण सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देना।

93. बैंकों को समग्र वित्तीय समावेशन की अवधारणा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से कुछ सरकारी क्षेत्र बैंकों के नक्शे कदम पर चलने और स्व-सहायता समूह के सदस्यों की सभी ऋण संबंधी आवश्यकताएं अर्थात् (क) आय उपार्जक क्रियाकलाप, (ख) सामाजिक आवश्यकताएं जैसे आवास, शिक्षा, विवाह आदि; और (ग) ऋण अदला-बदली की आवश्यकताओं को पूरा करने का अनुरोध करेगी।

नाबार्ड, सिडबी तथा एनएचबी

94. वित्तीय समावेशन को, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी की पहुंच में विस्तार करके आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इन तीनों बैंकों का संसाधन आधार बढ़ाने के लिए, मैं अनुसूचित बैंकों के संसाधनों का उस हद तक उपयोग करने का प्रस्ताव करता हूँ, जब तक वे प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने की अपनी बाध्यता को पूरा नहीं कर पाते। तदनुसार निम्नलिखित निधियां गठित करने का प्रस्ताव रखा जाता है:

- (i) नाबार्ड में, इसकी अल्पावधिक सहकारी ऋण संस्थाओं को पुनर्वित्तपोषण कार्य में बढ़ोतरी करने के निमित्त 5,000 करोड़ रुपये की एक निधि;
- (ii) सिडबी में प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ की दो निधियां—एक जोखिम पूंजी वित्तपोषण और दूसरी एमएसएमई क्षेत्र की पुनर्वित्तपोषण क्षमता बढ़ाने के लिए; और
- (iii) ग्रामीण आवास क्षेत्र में इसके पुनर्वित्तपोषण कार्य बढ़ाने के लिए एनएचबी में 1,200 करोड़ रुपये की निधि।

इनमें से प्रत्येक निधि कुछ परिवर्तनों के साथ आरआईडीएफ के लिए प्रयोज्य सामान्य दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होगी।

95. विगत वर्ष मैंने लाभप्रद व्यवसायों में लगे हुए कमजोर वर्गों के समुदाय के लिए विभेदक ब्याज-दर (डीआरआई) योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा बढ़ाई थी। तथापि, मैंने पात्रता की सीमा नहीं बढ़ाई। यह अब भी 1986 में निर्धारित स्तर पर कायम है। इसे ठीक करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 24,000 रुपये वार्षिक आय वाले उधार लेने वाले परिवार की पात्रता सीमा निर्धारित करने के मापदण्ड का प्रस्ताव करता हूँ।

पूँजी बाजार

96. मैंने 2006 के अपने बजट भाषण में सदन को सूचित किया था कि आर.एच. पाटिल समिति की रिपोर्ट के आधार पर हम कारपोरेट बांडों के लिए एक एक्सचेंज व्यापारिक बाजार का सृजन करने के निमित्त कदम उठाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों ने कारपोरेट बांडों में व्यापार करने के लिए मंच बना लिए हैं।

97. कारपोरेट बांडों के लिए बाजार को विस्तारित करने हेतु कुछ और उपाय करते हुए, मैं इसमें आगे बढ़ने की मंशा रखता हूँ। इसलिए मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव रखता हूँ:

- बांड, मुद्रा और व्युत्पाद बाजारों को विकसित करने के लिए उपाय करना, जिनमें एक्सचेंज व्यापारिक मुद्रा और ब्याज दर भावी सौदे शामिल होंगे तथा उपयुक्त संरक्षण सहित पारदर्शी ऋण व्युत्पाद बाजार विकसित करना।
- ऐसा प्रक्रम लागू करके घरेलू परिवर्तनीय बांडों की कारोबारिता बढ़ाना, इससे निवेशक अंतर्निहित इक्विटी विकल्प को परिवर्तनीय बांड से अलग करने तथा इसका पृथक कारोबार करने में समर्थ होगा;
- अपनी जटिलता और अंतर्निहित जोखिमों पर आधारित वित्तीय लिखतों को वर्गीकृत करने हेतु बाजार आधारित प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करना; और

98. स्थायी खाता संख्या (पैन) का डर वस्तुतः समाप्त हो चुका है। पैन अब प्रतिभूति बाजार में सभी भागीदारों के लिए एकमात्र पहचान संख्या है। मैं उपयुक्त आरंभिक छूट सीमाओं के अधीन वित्तीय बाजार में सभी लेनदेनों के लिए पैन को आवश्यक बनाने के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

99. हमारे स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच उपलब्ध करते हैं। फिर भी हमारे पास प्रतिभूतियों के लिए एक परिपूर्ण राष्ट्रीय बाजार नहीं है क्योंकि राज्यों में स्टाम्प शुल्क की दरों के दायरे और प्रयोज्यता के बारे में मतभेद हैं। अतः मैं राज्यों के वित्तमंत्रियों की सशक्त समिति से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रतिभूतियों के लिए वास्तव में एक अखिल भारतीय बाजार बनाने हेतु केन्द्र सरकार के साथ मिलकर काम करें। इससे बाजार के आधार का विस्तार होगा और राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि होगी।

VI. अन्य प्रस्ताव

100. भारत 'जनसांख्यिकी लाभांश' प्राप्त करने की स्थिति में आ गया है क्योंकि 2008 में लगभग 77.5 करोड़ श्रमजीवी जनसंख्या है। इसके वर्ष 2026 में 95 करोड़ हो जाने की संभावना है। यदि कार्य बल, ज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था को पोषित करने हेतु कौशल प्राप्त न करें, तो यह लाभांश अवास्तविक हो सकता है।

कौशल विकास मिशन

101. वर्तमान समय में कई मंत्रालय/विभाग कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन और प्रबंध कर रहे हैं। मेरी मंशा इन क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों में हस्तक्षेप करने की नहीं है। तथ्य, एक विश्व स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम, मिशन मोड में आरंभ किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इससे विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार कौशल प्रदान करने की चुनौती का सामना किया जाएगा। मिशन की रूपरेखा और नेतृत्व इस प्रकार का होना चाहिए ताकि इसे सम्पूर्ण देश में शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके। अतः मैं लाभ न कमाने वाले निगम की स्थापना करने और उसे इस मिशन का कार्य सौंपने का प्रस्ताव करता हूँ। मेरी मंशा लगभग 15,000 करोड़ रुपये पूँजी के रूप में एकत्र करने की है, जो सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय स्रोतों से जुटाई जाएगी। मैं इस कार्य का आरंभ प्रस्तावित लाभ न कमाने वाले निगम में सरकार की इक्विटी के रूप में 1,000 करोड़ रुपये लगाकर करूँगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

102. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना के अन्तर्गत, 238 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जा रहा है। सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) योजना के अंतर्गत, 29 राज्यों में संगत-औद्योगिक भागीदारों सहित 309 आईटीआई की पहचान की गई है और 244 मामलों में करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ष 2008-09 में 300 और आईटीआई के उन्नयन की प्रत्याशा में, मैंने 750 करोड़ रुपये की राशि का अलग से प्रावधान किया है।

सैनिक स्कूल

103. मैं, रक्षा बलों में, विशेषकर अधिकारी स्तर पर आ रही कमी की दर से चिंतित हूँ। सैनिक स्कूलों ने रक्षा बलों के भावी भर्ती लीडरों और प्रशिक्षण के आधार के रूप में अद्वितीय भूमिका निभाई है। मैं, 22 सैनिक स्कूलों में प्रत्येक को कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और शारीरिक शिक्षा सुविधाओं सहित आधारभूत ढाँचे के तत्काल सुधार के लिए 2 करोड़ रुपये प्रति स्कूल की दर से 44 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

104. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्य सब्सिडी के लिए अगले वर्ष 32,667 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का अर्थ पर्याप्त आपूर्ति, उचित सब्सिडियाँ और सब्सिडीकृत खाद्य पदार्थों का कारगर वितरण करना होगा। मेरा विचार यह है कि लक्षित वर्ग को स्मार्ट कार्ड के जरिए सब्सिडियाँ प्रदान की जाएं। अंततः, मुझे दो इच्छुक भागीदार-हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र मिल गए हैं। वे क्रमशः हरियाणा और चंडीगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए प्रायोगिक आधार पर एक स्मार्ट कार्ड आधारित वितरण प्रणाली आरंभ करेंगे। मैं, हरियाणा के मुख्य मंत्री और चंडीगढ़ के प्रशासक का धन्यवाद करता हूँ और उन्हें इस प्रायोगिक योजना की सफलता के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का वचन देता हूँ।

असंगठित क्षेत्र के कामगार

105. असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी विधेयक, 2007 संसद के समक्ष विचारार्थ है। इस विधेयक के कानून बनने की आशा में, सरकार ने तीन योजनाएं आरंभ की हैं। इन्हें असंगठित क्षेत्र के कामगारों को चरणबद्ध तरीके से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। ये निम्नलिखित हैं;

- आम आदमी बीमा योजना, जिसे गरीब परिवारों को बीमा सुरक्षा मिलेगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जीवन बीमा निगम योजना के पहले वर्ष में 30 सितम्बर, 2008 तक एक करोड़ भूमिहीन परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु शामिल करेगा। मैंने एलआईसी को 1,000 करोड़ रुपए की राशि पहले ही दे दी है। दूसरे वर्ष में, एक करोड़ अन्य गरीब परिवारों को शामिल करने हेतु, मैं वर्ष 2008-09 में एलआईसी को 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव करता हूँ।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे 1 अप्रैल, 2008 से कार्यान्वित किया जाएगा।
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को इस योजना में शामिल करने हेतु 19 नवम्बर, 2007 से इसका विस्तार किया गया था। परिणामस्वरूप, इसका विस्तार 87 लाख लाभार्थियों से बढ़कर 157 लाख लाभार्थियों तक कर दिया गया है। मैं, इस संबंध में वर्ष 2007-08 में किए गए 2,392 करोड़ रुपए की राशि के आवंटन की तुलना में वर्ष 2008-09 में 3,443 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

गरीबों के लिए आवास

106. गरीबों के लिए आवास, भारत निर्माण के छः घटकों में से एक है और इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के जरिए इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। 60 लाख मकानों के लक्ष्य के मुकाबले, दिसम्बर, 2007 तक 41.13 लाख मकानों का निर्माण कर लिया गया है तथा मार्च 2008 के अंत तक 51.77 लाख मकानों का निर्माण हो जाएगा। भवन-निर्माण की उच्च लागत को देखते हुए, 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात स्वीकृत नए मकानों के संबंध में मैदानी इलाकों में प्रति इकाई सब्सिडी को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 35,000 रुपए और पर्वतीय/दुर्गम इलाकों में 27,500 रुपए से बढ़ाकर 38,500 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मकानों के उन्नयन के लिए सब्सिडी 12,500 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 15,000 रुपए की जाएगी। मकान को पूरा करने के लिए लाभार्थी को तब भी अपनी निधियों की आवश्यकता पड़ेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सलाह दी जाएगी कि वे इंदिरा आवास योजना के मकानों को विभेदक ब्याज दर के तहत शामिल करें और 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रति इकाई 20,000 रुपए की राशि का ऋण दें।

रक्षा

107. मैं रक्षा के लिए आवंटन को 10 प्रतिशत बढ़ाकर 96,000 करोड़ रुपए से 105,600 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैंने रक्षा मंत्री को आश्वासन दिया है कि रक्षा बलों के आवश्यक विशेषकर पूँजीगत व्यय के लिए उन्हें और अधिक राशि प्रदान की जाएगी।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

108. मौजूदा वर्ष में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में 5,800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। व्यय की गति को देखते हुए, मैं अगले वर्ष के लिए आवंटन को समान स्तर पर रखने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि इस राशि का लगभग 45 प्रतिशत बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों को आवंटित किए जाने की संभावना है।

जलवायु परिवर्तन

109. मैंने पिछले वर्ष के बजट भाषण में विशेषज्ञ समिति के गठन के सरकार के निर्णय की घोषणा की थी, जो भारत पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करेगी और उन उपायों की पहचान करेगी जो हमें भविष्य में करने पड़ सकते हैं। इस पर कार्य चल रहा है। "सामान्य परन्तु विशिष्टीकृत उत्तरदायित्व" के सिद्धान्त का पालन करते हुए भी हम अपने हित में कई कार्य कर सकते हैं और हमें अवश्य करने चाहिए। हम स्वच्छ प्रौद्योगिकी उत्पादों को बढ़ावा दे सकते हैं; हम ईंधन के उत्सर्जन और साधकता विनियमों की समीक्षा कर सकते हैं; हम ईंधन के लिए लकड़ी की बजाए सौर-ऊर्जा का सामान्य प्रयोग कर सकते हैं। हम गैस के उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं; जो सर्वोत्तम हाइड्रोकार्बन

है। हम कार्बन के उत्सर्जन के लिए व्यापारिक मंच की स्थापना कर सकते हैं; हम टिक्ज़क ग्रीनफील्ड शहरों का निर्माण कर सकते हैं; और हम काफी कुछ कर सकते हैं। इन्हें एवं अन्य विचारों के अन्वेषण तथा कार्यान्वयन के लिए सरकार एक स्थायी संस्थागत तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव करती है, जो विकास और समन्वयन की भूमिका निभाएगा। संस्थागत तंत्र के ब्यौरे की घोषणा शीघ्र की जाएगी।

छठा केन्द्रीय वेतन आयोग

110. मुझे बताया गया है कि छठा केन्द्रीय वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट 31 मार्च, 2008 तक प्रस्तुत करेगा। मुझे विश्वास है कि यह रिपोर्ट सरकारी कर्मचारियों की उचित अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

राष्ट्रमंडल खेल

111. राष्ट्रमंडल खेल आरंभ होने में केवल 947 दिन शेष हैं। वादे के अनुसार 2008-09 में हम 400 करोड़ रुपये प्रदान करेंगे। मैं संबंधित प्राधिकारियों से यह अनुरोध करता हूँ कि समय सीमाओं और गुणवत्ता मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाए।

उत्कृष्ट संस्थान

112. लगातार चौथे वर्ष के लिए, मैं तीन उत्कृष्ट संस्थानों में से प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2008-09 के पुरस्कार (i) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरि, महाराष्ट्र; (ii) मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर; और (iii) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

भारत की 'सॉफ्ट पावर'

113. भारत का संगीत, साहित्य, नृत्य, कला, पाक कला और विशेषकर फिल्में पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रही हैं। यह भारत की 'सॉफ्ट पावर' है और इसे अत्याधुनिक और प्रखर तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को एक कार्यक्रम तैयार करने और कार्यान्वित करने हेतु 75 करोड़ रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

बाघ संरक्षण

114. 1411 की संख्या एक चेतावनी की घंटी है। यह भारत के बाघों की संख्या है। बाघ का अस्तित्व संकट में है। बाघ संरक्षण के हमारे द्वारा किए जा रहे प्रयासों को पुनः तेज करने के लिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को 50 करोड़ रुपये के एकबारगी अनुदान का प्रस्ताव करता हूँ। इस अनुदान का अधिकांश भाग विशेष बाघ संरक्षण बल तैयार करने, उन्हें हथियार प्रदान करने और तैनात करने में उपयोग किया जाएगा।

मॉनिटरिंग और मूल्यांकन

115. सुदृढ़ आर्थिक विकास से कई नई चुनौतियाँ हमारे सामने आई हैं, एजेंसियों, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, जिला स्तर के अभिकरणों और अन्य कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को सवितरित बड़ी धनराशियों के प्रभावी मॉनिटरिंग, मूल्यांकन—और लेखा प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता संबंधी मेरा विचार है कि हम परिणामों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना परिचयों पर देते हैं, अथवा वास्तविक लक्ष्यों पर उतना ध्यान नहीं देते जितना वित्तीय लक्ष्यों पर देते हैं; अथवा गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं देते जितना परिमाण पर देते हैं। अतः सरकार का यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय आयोजना स्कीमों को मॉनिटर करने की प्रणाली शुरू की जाए। इसका कार्यान्वयन योजना आयोग की आयोजना स्कीम के रूप में किया जाएगा। एक व्यापक निर्णय सहायता प्रणाली और प्रबंधन सूचना प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। वर्ष 2008-09 में लगभग 1,000 केन्द्रीय आयोजना और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए योजनावार और राज्य वार राशियों का सृजन और मॉनिटर करना इसका आशयित परिणाम होगा।

116. सरकार मूल्यांकन को सुदृढ़ करना भी चाहती है। कुछ मंत्रालयों ने समवर्ती मूल्यांकन करना आरंभ किया है। अनुसंधान संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले स्वतंत्र मूल्यांकनों में अभिवृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। योजना आयोग प्रमुख योजनाओं के ऐसे मूल्यांकन प्राधिकृत करेगा और ग्यारहवीं योजना की मध्यावधिक समीक्षा तक यह कार्य पूरा करेगा।

VII. बजट अनुमान

117. अब मैं वर्ष, 2008-09 के बजट अनुमानों पर प्रकाश डालता हूँ।

118. आयोजना व्यय के संबंध में 243,386 करोड़ रुपये का अनुमान है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में यह 32.4 प्रतिशत होगा।

119. आयोजना-भिन्न व्यय का अनुमान 507,499 करोड़ रुपये है।

राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा

120. यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि देश की राजकोषीय स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मौजूदा वर्ष के लिए राजस्व घाटा 1.4 प्रतिशत (1.5 प्रतिशत के.ब.अ. की तुलना में) और राजकोषीय घाटा 3.1 प्रतिशत (3.3 प्रतिशत के.ब.अ. की तुलना में) होगा।

121. वर्ष 2008-09 में अधिक प्रगति होगी। वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्ति 602,820 करोड़ रुपए अनुमानित है और 658,118 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय होने का अनुमान लगाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, 55,298 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.0 प्रतिशत है। 133,900 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत है। माननीय सदस्यगण ध्यान देंगे कि मैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के तहत न केवल राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करूंगा, अपितु मैंने अपने लिए कुछ गुंजाइश भी रख छोड़ी है। राजस्व घाटे के मामले में, मैं 0.5 प्रतिशत के वार्षिक घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। तथापि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सेक्टर के लिए व्यय में सचेत परिवर्तन के कारण इसके लिए हमें संभवतः एक और वर्ष चाहिए। मेरे विचार से यह पूर्णरूप से स्वीकार्य स्थगन है।

राजकोषीय समंजन की कार्ययोजना का पुनर्निर्धारण

122. मैं यह मानता हूँ कि तेल, खाद्य और उर्वरक बांडों के कारण सरकार की महत्वपूर्ण देयताएं वर्तमान में आशा से नीचे हैं। यह लेखांकन प्रबन्ध पूर्व परम्परा के अनुकूल है। ऐसा होते हुए भी हमारा राजकोषीय और राजस्व घाटा उस सीमा तक कम आंका गया है। इन देयताओं को हमारे राजकोषीय लेखांकन में लाए जाने की जरूरत है। पहले उपाय के रूप में मैंने इन देयताओं को 'बजट का सार' में स्पष्ट रूप से दर्शाया है। छोटे केंद्रीय वेतन आयोग के कारण पड़ने वाले भार के स्पष्ट होने के बाद, मेरी मंशा तेरहवें वित्त आयोग से यह अनुरोध करने की है कि राजकोषीय समंजन की कार्ययोजना का पुनर्निर्धारण करें और समुचित रूप से संशोधित कार्ययोजना का सुझाव दें।

भाग - ख

VIII. कर प्रस्ताव

123. अध्यक्ष महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

124. अधिकांश लोग कर राजस्वों, विशेषकर प्रत्यक्ष करों में हुई अत्यधिक वृद्धि के प्रति आश्चर्यचकित हैं, मैं नहीं। मैंने सदैव यह कहा है कि भय अथवा पक्षपात रहित कर प्रशासन के साथ संतुलित और स्थिर कर दरों से राजकोष के राजस्व में अत्यधिक बढ़ोतरी होगी।

125. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को 2003-04 में 9.2 प्रतिशत का कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात विरासत में मिला। वर्ष 2007-08 के अन्त में, यह अनुपात बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो जाएगा।

126. उच्च विकास दरों से सहायता मिली है। व्यवहार में हुए परिवर्तनों ने भी मदद की है। इनसे अधिक सूचना प्रणाली और प्रौद्योगिकी सर्वाधिक सहायक रही है। और, यदि मैं विनोदपूर्ण बात कहूँ तो भाग्यशाली वित्त मंत्री होना भी शायद सहायक रहा है। हम अप्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों को प्राप्त करने और प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों को पार कर लिए जाने की ओर अग्रसर हैं। मैं इस अवसर पर सभी करदाताओं को धन्यवाद देता हूँ और उन्हें एक कारगर और करदाता अनुकूल प्रशासन देने का आश्वासन देता हूँ।

अप्रत्यक्ष कर

127. मैं, अब सीमा शुल्क से प्रारम्भ करता हूँ।

128. गैर-कृषि उत्पादों की अधिकतम दर जनवरी, 2004 में 20 प्रतिशत थी और अब यह 10 प्रतिशत है। यह संग्रहण दर घरेलू उद्योग के संरक्षण स्तर के सर्वाधिक निकट अनुमान है और सभी आयातों के संबंध में यह दर वर्ष 2006-07 में 10 प्रतिशत थी। अप्रैल, 2007 से, डालर के मुकाबले रुपए में 9.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इस स्तर पर अधिकतम दर घटाने की गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए, मैं सीमाशुल्क की अधिकतम दर में कोई परिवर्तन न करने का प्रस्ताव करता हूँ।

129. तथापि, मैं महसूस करता हूँ कि कुछ मामलों में, सीमा शुल्क को घटाना आवश्यक है ताकि सम्बद्ध उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा सके अथवा मूल्य वर्धन को प्रोत्साहन मिले अथवा विपर्यय या किसी विसंगति को दूर किया जा सके। मैं कुछ ऐसे मामलों का उल्लेख करूंगा।

130. मैं परियोजना आयातों पर सीमाशुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, मैं विद्युत क्षेत्र की कुछ विशिष्ट परियोजनाओं पर 4 प्रतिशत विशेष सीवीडी लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

131. कच्ची सामग्री की आपूर्ति में सुधार के लिए, मैं स्टील मेल्टिंग स्क्रेप और एल्यूमिनियम स्क्रेप पर शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव करता हूँ।

132. कतिपय निर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधियों और ऐसी औषधियों के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त प्रपुंज औषधियों पर, मैं सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने, साथ ही उन्हें पूर्णतः सीमाशुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

133. पशु तथा कुक्कट खाद्य सामग्री के विनिर्माण की लागत घटाने के लिए, मैं विटामिन प्रीमिक्सेज तथा खनिज मिश्रण पर शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत और फास्फोरिक एसिड पर 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

134. बेक्टोप्यूज पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य किया जाएगा। इससे दूध के भण्डार और उपयोग होने तक की अवधि बढ़ जाएगी और डेयरी उद्योग को फायदा मिलेगा।

135. मैं, सेट टाप बाक्सों के विशिष्ट पुर्जों और सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग में इस्तेमाल के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

136. सूचना/संचार क्षेत्र और मनोरंजन क्षेत्र में प्रयोग हो रहे उपकरणों के बीच समानता स्थापित करने हेतु, मैं, समाभिरूप उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

137. खेलों के सामान के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, मैं, निर्दिष्ट मशीनरी पर उत्पाद शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, खेलों के सामान के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

138. पिछले वर्ष उत्पाद शुल्क में की गई कमियों के फलस्वरूप, रत्न और जवाहरात उद्योग ने अच्छा परिणाम दिया है। मूल्यवर्धन और निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, खुरदरे क्यूबिक जिरकोनिया को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने और पालिश किए हुए क्यूबिक जिरकोनिया पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसी प्रकार, खुरदरे मुंगा पर उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

139. हेलीकाप्टर पायलटों के प्रशिक्षण को सुसाध्य बनाने के लिए, मैं, हेलीकाप्टर सिमूलेटरों पर उत्पाद-शुल्क हटाने का प्रस्ताव करता हूँ।

140. घरेलू उर्वरक उत्पादन में सहायता करने के लिए, मैं, कच्चे और अपरिष्कृत सल्फर पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

141. निर्यात प्रसुविधाओं और शुल्क छूटों की संयुक्त व्यवस्था की मेहरबानी से, नाफ्था का निर्यात रिफाइनरियों से किया जाता है और पॉलिमर विनिर्माताओं द्वारा नाफ्था का आयात किया जाता है जिससे कीमत में विकृति आती है और राजस्व हानियां होती हैं। मैं, पॉलिमरों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए नाफ्था पर शुल्क छूट वापस लेते हुए स्थिति सुधारने और इसे 5 प्रतिशत की सामान्य दर पर रखने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, उर्वरकों के उत्पादन के लिए आयातित नाफ्था को आयात शुल्क से छूट मिलती रहेगी।

142. अंततः क्रोम अयस्क के संरक्षण के लिए और भारत में इसे मूल्यवर्धित विनिर्माण के लिए उपलब्ध कराने हेतु, मैं, निर्यात शुल्क 2,000 रुपये प्रति मी. टन से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति मी. टन करने का प्रस्ताव करता हूँ।

143. मैं, अब उत्पाद शुल्कों का उल्लेख करता हूँ।

144. विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था का आधार होता है। उपभोग उत्पादन को संचालित करता है और उत्पादन निवेश को संचालित करता है। महसूस होता है कि उत्पादन और उपभोग की मौजूदा प्रवृत्तियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके, विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अतः, मैं, सभी वस्तुओं पर सामान्य सेनवैट दर 16 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

145. मैंने कुछ विशिष्ट क्षेत्र देखे हैं जहां वृद्धि धीमी हो रही है। ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे विकास और रोजगार के संचालक हैं। उनमें से कुछ के विस्तृत बाह्यकारक भी हैं। इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि :

- फार्मास्यूटिक क्षेत्र में उत्पादित सभी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना;
- बसों और उनकी चेसिस पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना;
- छोटी कारों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना और हाइब्रिड कारों पर उत्पाद शुल्क 24 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत की सामान्य संशोधित दर पर करना;
- दुपहियों और तिपहियों पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करना; और
- जिन यूनियों के पास संबद्ध बांस/काष्ठ सुगदी बनाने का संयंत्र नहीं है उनके लिए कागज, पेपर बोर्ड और उनसे अपारंपरिक कच्चे माल से विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना और 3,500 मी. टन तक की निकासियों पर और 8 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना। इसके अतिरिक्त, लेखन, मुद्रण और पैकिंग पेपर की कुछ किस्मों पर उत्पाद शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करना।

146. अनेक ऐसे उत्पाद हैं जो आम जनता के उपभोग की वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुओं पर कर समानता की जरूरत भी है। अनेक उद्योगों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, मैं, कम्पोस्टिंग मशीनों, वायरलैस डाटा कार्डों, पैक किए गए नारियल पानी, चाय और काफी मिश्रण और मुरमुरों सहित कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव करता हूँ।

147. इसके अलावा, मैं, जल शुद्धिकरण यंत्रों, परतों और फ्लश दरवाजों, जीवाणुहीन प्रसाधन गहियों आदि, निर्दिष्ट पैकेजिंग सामग्री और नाश्ते में इस्तेमाल किए जाने वाले अन्न सहित कुछ वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क 16 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

148. मैं, एड्स रोधी औषध, अटाजनवीर के साथ-साथ इसके विनिर्माण के लिए प्रपुंज दवाओं को उत्पाद-शुल्क से पूर्णतः छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

149. शीतागार सुविधाओं को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, मैं, 50 किलोवाट या अधिक की बिजली का उपयोग करने वाले 2 टीआर (टन रेफ्रिजेशन) से अधिक प्रशीतन उपस्कर (जिसमें कंप्रेसर, कंडेंसर यूनिट, इवैपोरेटर आदि शामिल हैं) पर अन्तिम प्रयोग आधार पर छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

150. मैं, प्रपुंज सीमेंट और पैकेज्ड सीमेंट पर उत्पाद-शुल्क दरों में समानता लाने का प्रस्ताव करता हूँ। तदनुसार, प्रपुंज सीमेंट पर अब 400 रुपए प्रति मीट्रिक टन अथवा 14 प्रतिशत यथामूल्य, जो भी अधिक हो, का उत्पादन शुल्क लगेगा। सीमेंट की ईंटों (क्लिकरों) पर 450 रुपए प्रति मीट्रिक टन का उत्पादन शुल्क देय होगा।

151. इसी प्रकार, मैं, पैकेज्ड सॉफ्टवेयर पर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे इसे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की बराबरी पर लाया जा सके, जिस पर 12 प्रतिशत सेवा कर लगेगा।

152. फिल्टर-रहित सिगरेटें, फिल्टर सिगरेटों से अधिक विषाक्त हैं, फिर भी उन्हें अनुकूल कर व्यवस्था का लाभ प्राप्त है, जो अनुचित है। मैं, फिल्टर और फिल्टर रहित दोनों सिगरेटों पर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने अनुमान लगाया होगा, उच्च दरों पर समान कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

153. दुष्प्रचार के स्रोत को हटाने के उद्देश्य से, मैं, अनब्रान्डेड पेट्रोल और अनब्रान्डेड डीजल पर उत्पाद शुल्क के यथा मूल्य भाग को समाप्त करने और उसके स्थान पर 1.35 रुपए प्रति लीटर का एक समान विशिष्ट शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। अब से, अनब्रान्डेड पेट्रोल पर 14.35 रुपए प्रति लीटर और अनब्रान्डेड डीजल पर 4.60 रुपए प्रति लीटर का केवल एक विशिष्ट शुल्क होगा। खुदरा मूल्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

154. इस समय, एनसीसीडी नामक 1 प्रतिशत का उत्पाद-शुल्क पोलिएस्टर फिलामेंट धागे पर लगाया जाता है। यह इस उत्पाद-शुल्क को वहन करने वाला अकेला धागा है। मैं, इस शुल्क को हटाकर इसे सेल्युलर मोबाइल फोनों पर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

155. अन्ततः, मैं, सेवा कर संबंधी अपने प्रस्तावों पर आता हूँ।

156. सेवा क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में 55 प्रतिशत का योगदान किया जाता है। यह एक वृद्धिशील क्षेत्र है जिसे राजकोष में अपना उचित योगदान अवश्य करना चाहिए। मैं, चार सेवाओं को सेवाकर के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूँ। ये हैं :

- (i) यूलिप के अंतर्गत प्रदत्त आस्ति प्रबंधन सेवा, ताकि इसे म्युचुअल फंडों के अधीन प्रदत्त आस्ति प्रबंधन सेवा के समकक्ष लाया जा सके;
- (ii) स्टॉक/पण्य एक्सचेंजों और समाशोधन गृहों द्वारा प्रदत्त सेवाएं ;
- (iii) उन मामलों में जहां वेट देय नहीं हैं, वस्तुओं का प्रयोग करने का अधिकार; और
- (iv) कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, जिससे इसे पैकेज्ड सॉफ्टवेयर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के बराबर लाया जा सके।

157. मैं, कतिपय सेवाओं के संबंध में उठाई गई अवांछित शंकाओं को दूर करने और यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव करता हूँ कि उन पर सेवाकर लगाना चाहिए। इनमें मनी चेंजर, दांव का खेल चलाने वाले व्यक्ति और कॉन्ट्रेक्ट कैरिज वाहनों का प्रयोग करने वाले दूर आपरेटर शामिल हैं।

158. कुछ विधि परिवर्तन हैं जिन पर मैं, सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ।

159. अन्ततः, मुझे यह घोषित करते हुए प्रसन्नता है कि लघु सेवा प्रदाताओं के लिए छूट की आरंभिक सीमा 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की जाएगी। परिणामस्वरूप, लगभग 65,000 लघु सेवा प्रदाता कर दायरे से निकल जाएंगे।

प्रत्यक्ष कर

160. अब मैं प्रत्यक्ष करों पर आता हूँ।

161. मैं 2007 के बजट भाषण का स्मरण दिलाता हूँ। मेरा विश्वास है कि साहस काम आता है। मेरा यह भी मानना है कि विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। नियंत्रण से राजस्व और निष्पक्षता से अनुपालन होगा। आय कर दाताओं ने कुछ राहत के विषय में एक आकर्षक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तदनुसार मैं, वैयक्तिक आयकर स्लैबों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं छूट की आरंभिक सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ :

- सभी निर्धारितियों के मामले में 1,10,000 रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए की जाए, इस प्रकार प्रत्येक निर्धारिती को न्यूनतम 4,000 रुपए की राहत मिल जाएगी। परिणामस्वरूप, तीन श्रेणियां और कर-दरें निम्नानुसार होंगी :

1,50,000 रुपए तक	शून्य
1,50,001 रुपए से 3,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
5,00,001 रुपए और अधिक	30 प्रतिशत

- महिला निर्धारित के मामले में 1,45,000 से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए की जाए;
- वरिष्ठ नागरिक के मामले में 1,95,000 रुपए से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए की जाए।

162. कारपोरेट आय कर की दरों में, मैं कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ।

163. अधिभार की दर में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

164. मैं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004 और डाकघर मियादी जमा खाता को आय कर अधिनियम की धारा 80G के तहत बचत लिखतों के वर्ग में रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

165. ऐसे व्यक्ति, जो अपने माता-पिता के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है, के लिए, मैं धारा 80घ के तहत 15,000 रुपए की अतिरिक्त कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

166. मौजूदा वित्त वर्ष में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रतिवर्ती बंधक योजना अधिसूचित की गई। इस योजना से उत्पन्न कर मुद्दों का समाधान करने के लिए, मैं आय कर अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे निम्नलिखित की व्यवस्था हो :

(i) प्रतिवर्ती बंधक 'अंतरण' नहीं होगा; और

(ii) वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त राजस्व को आय नहीं माना जाएगा।

167. कृषि आय आयकर से छूट प्राप्त है। तथापि, न्यायालयों ने यह व्यवस्था दी है कि भूमि पर पौध लगाकर अथवा बुआई करके उगाना कृषि है किन्तु उन्हें गमलों में उगाना कृषि नहीं है। यह उचित नहीं लगता। अतः मैं, पौधशाला में पौध लगाकर अथवा बुआई करके उगाए गए पौधों से अर्जित आय पर कर में छूट देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

168. कतिपय कारबारों में लगी कंपनियों को आंतरिक वैज्ञानिक अनुसंधान पर होने वाले किसी व्यय पर 150 प्रतिशत भारित कटौती की अनुमति है। मैं इस सूची में बीजों का उत्पादन और कृषि साधनों के विनिर्माण को शामिल करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

169. अनुसंधान की आउट-सोर्सिंग को संबंधित करने के लिए, अनुसंधान और विकास कार्यों में लगी कंपनियों को किए जाने वाले किसी भी भुगतान पर 125 प्रतिशत भारित कटौती अनुमत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

170. मैं सेवा क्षेत्र में निर्धारितियों को धारा 35घ के अंतर्गत कुछ प्राथमिक खर्चों के परिशोधन के लाभों के विस्तार की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ।

171. कारपोरेट ऋण बाजार के संबंध में मेरे द्वारा पहले घोषित किए गए उपायों में अभिवृद्धि के लिए, मैं डीमैट रूप में जारी और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कारपोरेट ऋण लिखतों को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट देने का प्रस्ताव रखता हूँ।

172. मैं अनुषंगी लाभ कर (एफबीटी) से संबंधित कानून के उपबंधों में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव रखता हूँ जिससे कारपोरेट और फर्मों को कुछ राहत मिलेगी। शिशु सदन सुविधाएं, किसी खिलाड़ी कर्मचारी का प्रायोजन, कर्मचारियों के लिए खेलकुद प्रतियोगिताओं का आयोजन और अतिथि गृहों को एफबीटी के दायरे से बाहर किया जाएगा।

173. इस समय, घरेलू कंपनी लाभांश वितरण कर (डीडीटी) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। परिणामस्वरूप, वितरित लाभांश पर कभी-कभी सहायक कंपनी और इसकी मूल कंपनी के हाथों दो बार कर लग जाता है जिससे दिक्कतें पैदा होती हैं। इस दिक्कत को दूर करने के उद्देश्य से, मैं मूल कंपनी को इसकी सहायक कंपनी से प्राप्त लाभांश का समर्जन मूल कंपनी द्वारा वितरित लाभांश में से करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ, परन्तु यह कि प्राप्त लाभांश पर डीडीटी लागू किया गया हो और मूल कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी न हो।

174. मैं, शहरी समूहों के बाहर किसी स्थान में स्थित अस्पतालों को पंचवर्षीय करावकाश प्रदान करने के लिए धारा 80इख में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ, और ये विशेषतः टियर-2 और टियर-3 शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों को अपनी सेवाएं देंगे। यह अवसर 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2013 की अवधि के लिए खुला होगा जिससे पूर्व, अस्पताल को कामकाज शुरू करना होगा।

175. पर्यटकों, विशेषकर सांस्कृतिक पर्यटन के लिए, संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी को देखते हुए, मैं यूनेस्को द्वारा घोषित 'विश्व विरासत स्थलों' के विनिर्दिष्ट जिलों में स्थापित दो, तीन अथवा चार सितारा होटलों को आयकर से पांच वर्ष का करावकाश प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। होटल का निर्माण और कार्य आरंभ 1 अप्रैल, 2008 और 31 मार्च, 2013 के बीच की अवधि में होना चाहिए।

176. मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि कयर बोर्ड को धारा 10(29क) में शामिल किया जाएगा और वह आय कर के दायरे से बाहर हो जाएगा।

177. बांटे गए लाभांशों पर 15 प्रतिशत कर लगता है। अल्पावधिक पूंजी लाभों पर धारा 111क के अंतर्गत 10 प्रतिशत कर लगता है। दरों को समान करने में अच्छाई है, इसीलिए मैं धारा 111क और 115कघ के अंतर्गत अल्पावधिक पूंजी लाभों पर कर की दर बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह निवेशकों को दीर्घावधि के लिए निवेशित रहने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

178. वर्तमान में, भुगतान किए गए प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) की अनुमति, कर देयता में छूट के रूप में प्राप्त है। इसके अलावा, ऑप्शनों पर एएटीटी, स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन प्रीमियम के कुल योग पर लगाया जाता है और इसे विक्रेता द्वारा वहन किया जाता है। मैं, इस में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब से, भुगतान किए गए एसटीटी को व्यापार आय में से किसी अन्य कटौती योग्य व्यय के रूप में माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऑप्शनों के मामले में, एसटीटी का उद्ग्रहण केवल इस ऑप्शन पर किया जाएगा, जहां ऑप्शन का प्रयोग न किया गया हो और यह देयता विक्रेता पर होगी। प्रयोग किए गए ऑप्शन के मामले में कर, निपटान मूल्य पर लगाया जाएगा और देयता क्रेता पर होगी। वर्तमान दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

179. वस्तुओं के भावी सौदों में लेन-देन का युग आ गया है। अतः मैं ऑप्शनों और फ्यूचरों पर एसटीटी की तर्ज पर पण्य लेन-देन कर (सीटीटी) आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूँ।

180. 'धर्मार्थ प्रयोजन' में गरीबों को राहत, शिक्षा, चिकित्सा संबंधी राहत और इसी प्रकार का अन्य कार्य शामिल है। इन कार्यों को कर से मुक्त रखा गया है, जैसाकि होना चाहिए। तथापि, कुछ कंपनियों, जो किसी कारोबार, वाणिज्य अथवा व्यापार संबंधी कोई नियमित कारोबार, वाणिज्य अथवा व्यापार चला रही है अथवा इनके विषय में सेवा प्रदान कर रही है और आय का अर्जन कर रही हैं, ने यह दावा किया है कि उनके प्रयोजन भी 'धर्मार्थ प्रयोजन' की श्रेणी में आएंगे। स्पष्ट रूप से यह संसद की मंशा नहीं थी और इसलिए मैं उपर्युक्त मामलों को शामिल न किए जाने हेतु कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ। वास्तविक धर्मार्थ संगठन किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे।

181. बैंकिंग नकद लेन-देन कर (बीसीटीटी) आय कर विभाग की सूचना प्रणाली को बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी रहा है। चूंकि सूचना, विगत कुछ वर्षों में शुरू किए गए अन्य लिखतों के जरिए भी एकत्र की जा रही है, अतः 1 अप्रैल, 2009 से मैं इस कर को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

182. प्रत्यक्ष करों के संबंध में मेरे कर प्रस्तावों से राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु अप्रत्यक्ष करों के संबंध में प्रस्तावों से 5,900 करोड़ रुप की हानि होने का अनुमान है।

केन्द्रीय बिक्री कर और वस्तु एवं सेवा कर संबंधी कार्य योजना

183. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच हुए करार के पश्चात् केन्द्रीय बिक्री कर की दर इस वित्त वर्ष में 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की गई थी। अब इसे 1 अप्रैल, 2008 से घटाकर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। हानियों, यदि कोई हों, की क्षतिपूर्ति के संबंध में बातचीत चल रही है और यदि करार हो जाता है तो नई दर अधिसूचित की जाएगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर आरंभ करने के लिए कार्य योजना तैयार करने में पर्याप्त प्रगति हुई है।

IX. निष्कर्ष

184. अध्यक्ष महोदय, किसी समय विश्व के उत्पादन में भारत और चीन का योगदान 50 प्रतिशत था। हमें अपनी पुनः स्थिति प्राप्त करनी चाहिए और ऐसा करने की हमारे अन्दर क्षमता है।

185. सरकार में हमारा कार्य प्रतिदिन प्रति घंटा संपूर्ण रोजगार, गरीबी उन्मूलन और असमानता को समाप्त करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग की खोज करना है। 'ये लक्ष्य राष्ट्रीय आय में पर्याप्त वृद्धि से प्राप्त किए जा सकते हैं और इसीलिए हमारी आर्थिक नीति का लक्ष्य भरपूर और उचित वितरण होना चाहिए। हमें धन का उपार्जन करना और तत्पश्चात् उसका उचित बंटवारा करना चाहिए। धन के बिना, हम कल्याणकारी राज्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये मेरे शब्द नहीं हैं; ये शब्द वर्ष 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, परन्तु समावेशी विकास वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि, वास्तव में उन्होंने उसकी दशाओं का वर्णन किया था।

186. ये शब्द संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। ठीक वैसे ही जैसाकि मैं मार्गदर्शन और आश्वासन के लिए हमेशा संत तिरुवल्लुवर की शरण में जाता हूँ। 2000 वर्ष पहले, उन्होंने निम्नलिखित अमर वाणी में अच्छे शासन के लिए निर्देशचिन्ह निर्धारित किया है :

“कोडुयई आन्ऱु सिंगोल कुडी ओम्बल
नांगुम उड्यनम वेन्ऱक्कु ओली”

[उदारता से दान, भावग्राही, उत्तम व्यवस्था और
पददलितों का सहायक सुशासन की पहचान हैं]

हमने इस दर्शन के प्रति ईमानदार रहने के प्रयास किए हैं। चार वर्षों में 2007-08 अब तक का सर्वोच्च वर्ष रहा है, परन्तु मैं विनम्रता से कहता हूँ कि अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं हुआ है।

187. महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूँ।

एल. एम. वास, अतिरिक्त सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2008

No. F. 2(11)-B(D)/2008.—The following is published for general information :—

Budget 2008-2009

Speech of

P. CHIDAMBARAM

Minister of Finance

February 29, 2008

Mr. Speaker, Sir

I rise to present the Budget for 2008-09. This House and the United Progressive Alliance Government have bestowed upon me the honour of presenting all five Budgets on behalf of a Government—a rare honour that I have the privilege to share with only one of my distinguished predecessors, Dr. Manmohan Singh.

I. THE ECONOMY: AN OVERVIEW

2. Honourable Members! The India growth story, so far, has been an absorbing and inspiring tale. Beginning January 1, 2005, the economy has recorded a growth rate of over 8 per cent in 12 successive quarters up to December 31, 2007. In the first three years of the UPA Government, the Gross Domestic Product (GDP) increased by 7.5 per cent, 9.4 per cent and 9.6 per cent, resulting in an unprecedented average growth rate of 8.8 per cent. In the current year too, according to the Advance Estimates by the Central Statistical Organisation (CSO), the growth rate will be 8.7 per cent - although I am confident that we will maintain the average of 8.8 per cent. The drivers of growth continue to be “services” and “manufacturing”, which are estimated to grow at 10.7 per cent and 9.4 per cent, respectively.

3. Nevertheless, 2007-08 has been the most challenging of the last four years. At the beginning of the year, the outlook for the global economy was benign. Our economy, thanks to our own policies as well as globalisation, was poised to record another year of high growth: in fact, the first half of 2007-08 returned a growth of 9.1 per cent. However, since August 2007, the financial markets in the developed countries have witnessed considerable turbulence that has not yet abated. The consequences for developing countries are also not yet clear.

4. Moreover, agriculture has struck a disappointing note. Despite a fine start in the first half of 2007-08, the growth rate for the whole year in agriculture is estimated at only 2.6 per cent.

5. There are other downside risks too. World prices of crude oil, commodities and food grains have risen sharply in the period April 2007 to January 2008. The position of crude oil is well known to this House. Among commodities, the prices of iron ore, copper, lead, tin, urea etc. are elevated. The prices of wheat and rice have increased in the world market by 88 per cent and 15 per cent, respectively. All these trends are inflationary, and there is pressure on domestic prices, especially on the prices of food articles. Consequently, the management of the supply side of food articles will be the most crucial task in the ensuing year.

6. We have also witnessed capital inflows that are far in excess of the current account deficit. This poses a challenge to monetary management. The solution lies in increasing the absorptive capacity of the economy in the medium term. In the short term, it is our responsibility to manage the flows more actively. Government will, in consultation with the RBI, continue to monitor the situation closely and take such temporary measures as may be necessary to moderate the capital flows consistent with the objective of monetary and financial stability.

7. Keeping inflation under check is one of the cornerstones of our policy. Recently, the Prime Minister declared, “I think no Government in our country can be oblivious to the objective of ensuring reasonable price stability without hurting the growth process.” There can be no clearer enunciation of policy. However, since the downside risks have increased worldwide, we must be vigilant and prepared to make swift adjustments in our policies to achieve the goal of growth with price stability.

8. Let me first deal with agriculture, briefly for the present, and at some length later. The Ministry of Agriculture has estimated that the total output of food grains in 2007-08 will be 219.32 million tonnes and that will be an all time record. In

particular, production of rice is estimated at 94.08 million tonnes; maize at 16.78 million tonnes; soya bean at 9.45 million tonnes; and cotton at 23.38 million bales (of 170 kg. each)—and each of these will be an all time record. Government is conscious that while a lot has been done, a lot more needs to be done. Since the last Budget, Government has formulated and announced the National Policy for Farmers. Besides, Government has launched the Rashtriya Krishi Vikas Yojana with an outlay of Rs. 25,000 crore and the National Food Security Mission with an outlay of Rs. 4,882 crore. Both Schemes will be implemented during the Eleventh Five Year Plan period. We are determined to become self-sufficient in food grains. Presently, I shall place before this House a number of new initiatives in the agriculture sector.

The Growth Story : Faster and more inclusive

9. To return to the India growth story, I am of the firm belief that we owe our sustained progress to the policy of economic reforms first ushered in by a Congress Government and now carried forward by the UPA Government.

10. If 1984 and 1991 were turning points in the history of India's economy, 2004 was another turning point. Confident that high growth was sustainable, the UPA Government had declared in the National Common Minimum Programme its intention to make growth more inclusive. Sir, I ask this House, respectfully, to judge our record on inclusive growth from the following sample of facts:

- agricultural credit doubled in the first two years of this Government and is poised to reach a level of Rs. 240,000 crore by March 2008.
- the National Rural Employment Guarantee Scheme has proved to be a historic measure of empowerment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and, especially, of women.
- the Mid Day Meal Scheme is the largest school lunch programme in the world covering 11.4 crore children.
- the National Rural Health Mission has taken improved health care to rural India by strengthening the primary health centres of which 8,756 have been made 24 × 7.
- the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Scheme has enrolled 182,000 girls in residential schools, thus helping to bridge the gender gap in education.

Bharat Nirman

11. Bharat Nirman has made impressive progress in 2007-08. This ambitious programme is now over 1,000 days old. At the current pace, on each day of the year 290 habitations are provided with drinking water and 17 habitations are connected through an all weather road. On each day of the year 52 villages are provided with telephones and 42 villages are electrified. On each day of the year 4,113 rural houses are completed.

12. Mr. Speaker, just as I sat down to write this speech, I received a slim volume titled "Indira Gandhi - Selected Sayings". Within minutes, I found this gem and I quote, "The more one does, the more one attempts, the more one is capable of doing". What I have narrated so far is indeed proof of more inclusive growth, but if you ask me "can we do better?", my answer would be "we can and we should." Budget 2008-09 is about raising our sights and doing more and doing better.

II. THE ELEVENTH FIVE YEAR PLAN: THE CRUCIAL SECOND YEAR

13. The Eleventh Plan has started on a note of robust growth. Never before did we start a Plan with a first year growth rate of 8.7 per cent. Government regards the second year of the Plan as extremely critical to the success of the Plan. 2008-09 should be a year of consolidation; of securing the ongoing programmes on firm financial foundations; of close monitoring of implementation and enforcing accountability; and of measuring the outcomes in terms of the targets achieved as well as their quality. The Plan documents assumed that the Gross Budgetary Support (GBS) in the second year would be Rs. 228,725 crore. In our view, that will not be enough. Hence, I propose to increase the GBS to Rs. 243,386 crore, which will represent an increase of Rs. 38,286 crore over the allocation in 2007-08.

14. Out of the GBS, the allocation for the Central Plan will be Rs. 179,954 crore, marking an increase of 16 per cent over 2007-08.

15. Let me assure the House that all ongoing programmes will receive ample funds.

16. For Bharat Nirman, I propose to provide Rs. 31,280 crore [including the North Eastern Region (NER) component] as against Rs. 24,603 crore in 2007-08.

Education: Sarva Shiksha Abhiyan

17. Education and health are the twin pillars on which rests the edifice of social sector reforms. The total allocation for the education sector (including NER) will be increased by 20 per cent from Rs. 28,674 crore in 2007-08 to Rs. 34,400 crore in 2008-09.

18. Of this, Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) will be provided Rs.13,100 crore; the Mid-day Meal Scheme will be provided Rs.8,000 crore; and secondary education will be provided Rs. 4,554 crore.

19. The focus of SSA will shift from access and infrastructure at the primary level to enhancing retention; improving quality of learning; and ensuring access to upper primary classes.

20. A Model School programme, with the aim of establishing 6,000 high quality model schools, will be started in 2008-09. I propose to provide Rs. 650 crore for the new scheme.

Jawahar Navodaya Vidyalaya

21. Jawahar Navodaya Vidyalayas are quality schools. In order to make such schools more accessible to SC and ST students, Government plans to establish Navodaya Vidyalayas in 20 districts that have a large concentration of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I propose to set apart Rs.130 crore in 2008-09 for this purpose.

Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya

22. Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas were set up to address the issue of equity in the education of girls belonging to SC, ST, OBC and minority communities. So far, 1,754 vidyalayas have been started, and I propose to allocate funds (as part of SSA) to set up an additional 410 vidyalayas in educationally backward blocks. I also propose to provide a sum of Rs.80 crore to set up new or upgrade existing hostels attached to the Balika Vidyalayas.

National Means-cum-Merit Scholarship

23. Last year, I had announced the National Means-cum-Merit Scholarship Scheme to enable students to continue their education beyond class VIII and up to class XII. I had provided Rs.750 crore with the promise to add a like amount every year for three more years. The Scheme will be implemented by award of 100,000 scholarships beginning 2008-09. I intend to keep my promise and earmark another sum of Rs. 750 crore so that a corpus of Rs. 3,000 crore will be built up in four years.

Nehru Yuva Kendra

24. 123 districts do not have a Nehru Yuva Kendra. I propose to allocate Rs.10 crore in 2008-09 to set up a Kendra in each of these districts and to cover the recurring expenditure in the first year.

Mid-day Meal Scheme

25. The Mid-day Meal Scheme has been extended to upper primary classes in 3,479 educationally backward blocks. The scheme will now be extended to upper primary classes in Government and Government-aided schools in all blocks in the country. This will benefit an additional 2.5 crore children, taking the total number of children covered under the Scheme to 13.9 crore.

Institutes of Higher Education

26. Knowledge is power. It is knowledge that will drive success in the 21st century. India has the opportunity to become a knowledge society. Following the Prime Minister's announcement, an IIM at Shillong; three IISERs at Mohali, Pune and Kolkata; and an IIIT at Kanchipuram have started functioning. Government will establish one Central University in each of the hitherto uncovered States. We propose to make a beginning in 2008-09 by establishing 16 Central Universities. Besides, we propose to set up three IITs in Andhra Pradesh, Bihar and Rajasthan; two IISERs at Bhopal and Tiruvananthapuram; and two Schools of Planning and Architecture at Bhopal and Vijayawada. More institutes of higher education, as promised by the Prime Minister, will be established during the Eleventh Plan period.

27. I also propose to make a grant of Rs.5 crore to the Deccan College Post-Graduate and Research Institute, Pune which is one of the oldest institutions of modern learning in India.

Science and Technology

28. We must encourage our children to take to careers in science and research and development. Ministry of Science and Technology will introduce a scheme called Innovation in Science Pursuit for Inspired Research (INSPIRE) that will include scholarships for young learners (10-17 years), scholarships for continuing science education (17-22 years) and opportunities for research careers (22-32 years). I propose to provide Rs.85 crore in 2008-09 for this inspired contribution to building a knowledge society.

29. The recommendations of the National Knowledge Commission, submitted from time to time, are under active

consideration. Some of them have been incorporated in the Eleventh Plan. Government has accepted an important recommendation to inter-connect all knowledge institutions through an electronic digital broadband network. This will encourage sharing of resources and collaborative research. I propose to provide Rs. 100 crore to the Ministry of Information and Technology for establishing the National Knowledge Network.

Health

30. Turning to the health sector, I propose to allocate Rs.16,534 crore for the sector (including NER). This will mark an increase of 15 per cent over the allocation in 2007-08.

National Rural Health Mission

31. The National Rural Health Mission (NRHM) is the key instrument of intervention by the Central Government. The goal is to establish a fully functional, community owned, decentralised health delivery system. 462,000 Associated Social Health Activists (ASHAs) and link workers have been trained and are in place. 177,924 Village Health and Sanitation Committees are functional. 323 district hospitals have been taken up for upgradation. Ambitious goals have been set for 2008-09, and I propose to increase the allocation for NRHM to Rs.12,050 crore.

HIV/AIDS

32. The National Aids Control Programme will be provided Rs.993 crore. Studies have shown that the prevalence rate of HIV/AIDS has come down from 0.9 per cent to 0.36 per cent, which is a matter of some satisfaction.

Polio

33. The drive to eradicate polio continues with a revised strategy and a focus on the high risk districts in Uttar Pradesh and Bihar. I propose to provide Rs.1,042 crore in 2008-09 for this purpose.

Rashtriya Swasthya Bima Yojana

34. Two major interventions are planned to be started in 2008-09. The first is the Rashtriya Swasthya Bima Yojana that will provide a health cover of Rs.30,000 for every worker in the unorganised sector falling under the BPL category and his/her family. I am happy to report that most of the States have agreed to join the Yojana and it will be launched in Delhi and in the States of Haryana and Rajasthan on April 1, 2008. I propose to provide Rs. 205 crore as the Centre's share of the premia in 2008-09.

National Programme for the Elderly

35. The other major intervention will be for the elderly. A National Programme for the Elderly with a Plan outlay of Rs.400 crore will be started in 2008-09. Among other measures, we will establish, during the Eleventh Plan period, two National Institutes of Ageing, eight regional centres, and a department for geriatric medical care in one medical college/tertiary level hospital in each State.

Integrated Child Development Services

36. The universalization of the Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme is underway. At the end of December 2007, 5,959 ICDS projects and 932,000 Anganwadi and mini-Anganwadi centres were functional. The beneficiary count had increased to 629 lakh children and 132 lakh pregnant and lactating mothers. I propose to enhance the allocation for ICDS from Rs. 5,293 crore in 2007-08 to Rs. 6,300 crore in 2008-09.

37. I am also happy to announce that the remuneration of Anganwadi workers will be increased from Rs. 1,000 per month to Rs.1,500 per month. Likewise, the remuneration of Anganwadi Helpers will be increased from Rs.500 per month to Rs.750 per month. Over 18 lakh Anganwadi workers and helpers will benefit from the increase.

Flagship Programmes

38. As Honourable Members are aware, there are eight flagship programmes of the UPA Government. I have dealt with two in the education sector (SSA & MMS) and two in the health sector (NRHM & ICDS). Let me now refer to the allocations that I propose to make for the other four flagship programmes:

- The National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) will be rolled out to all 596 rural districts in India. Initially, we will provide Rs.16,000 crore. Let there be no apprehension in anyone's mind: as demand rises, more money will be provided to meet the legal guarantee of employment.
- The Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) is the main vehicle for improving urban infrastructure. It has also succeeded in driving reforms in urban governance and urban-related laws. I propose to increase the allocation from Rs.5,482 crore in 2007-08 to Rs.6,866 crore in 2008-09.

- The goal of the Rajiv Gandhi Drinking Water Mission is to supply safe drinking water to uncovered habitations and slipped back habitations as well as to address issues of quality. I propose to enhance the allocation to Rs. 7,300 crore in 2008-09 as against Rs. 6,500 crore in 2007-08.

The Mission does not yet have a separate component for school children in water-deficient habitations. Our children should have good, clean drinking water. Hence, I propose to allocate funds to the Mission under a separate sub-head in order to install a standalone system to provide potable water to each school in water-deficient habitations. The cost of each system, depending on the technology and design, is estimated to be between Rs. 15,000 to Rs. 30,000. While a detailed plan for four years will be drawn up, I propose to make an initial allocation of Rs. 200 crore in 2008-09.

- The Total Sanitation Campaign is all about changing habits and mindsets, and it is a continuous process. I propose to provide Rs. 1,200 crore in 2008-09.

Desalination Plant

39. Honourable Members will recall that I had in July 2004 announced support for a desalination plant to be installed near Chennai. A proposal has now been received from the Government of Tamil Nadu to establish a plant under public private partnership. While the proposal will be examined for approval, I propose to signal the Government's support to the project by setting apart Rs. 300 crore in 2008-09.

North Eastern Region

40. The North Eastern Region (NER) will continue to receive special attention and enhanced allocations. I propose to provide Rs. 1,455 crore to the Ministry of Development of North Eastern Region (DONER). Including that amount, the total Budget allocation for NER, spread over different ministries/departments, will increase from Rs. 14,365 crore in 2007-08 to Rs. 16,447 crore in 2008-09.

41. The North Eastern Region and, especially, Arunachal Pradesh and the border areas face special problems that cannot be tackled in the usual course or through normal schemes. Hence, Government proposes to identify the urgent needs of these areas and address them through a special mechanism. In order to jumpstart the process, I propose to set apart a sum of Rs. 500 crore in a fund dedicated for the purpose.

SC, ST, OBC and Minorities

42. Scheduled Castes, Scheduled Tribes, socially and educationally backward classes, and minorities will continue to receive special attention.

Development and Finance Corporations

43. Development and Finance Corporations have been set up for certain disadvantaged groups. I propose to contribute additional equity to these corporations in the following manner :

	Rs. Crore
1. National Minorities Development and Finance Corporation	75.00
2. Three National Finance and Development Corporations for Weaker Sections comprising :	106.50
(i) Safai Karamcharis	
(ii) Scheduled Castes	
(iii) Backward Classes	
3. National/State Scheduled Tribes Finance and Development Corporations	50.00
4. National Handicapped Development Corporation	9.00

Scholarships

44. In previous Budgets, we had announced a slew of pre and post-matric scholarship programmes for SC, ST, OBC and minorities. All of them will be continued in 2008-09 with adequate funds as summarised below :

Scheduled Castes	Rs. 804 crore
Scheduled Tribes	Rs. 195 crore
Other Backward Classes	Rs. 164 crore
Minorities (post-matric)	Rs. 100 crore

45. I propose to allocate a sum of Rs.75 crore in 2008-09 to the Rajiv Gandhi National Fellowship Programme. As Honourable Members are aware, this programme supports SC and ST students pursuing M.Phil and Ph.D courses.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes

46. Following the practice initiated in 2005-06, I have included in the Budget documents a statement on the schemes for the welfare of SCs and STs. I have provided Rs. 3,966 crore for schemes benefiting SCs and STs exclusively and Rs.18,983 crore for schemes where at least 20 per cent of the benefits are earmarked for SCs and STs.

Minorities

47. The allocation to the Ministry of Minority Affairs will be increased from Rs. 500 crore in 2007-08 to Rs. 1,000 crore in 2008-09. Government has taken up the report of the Justice Rajindar Sachar Committee for speedy implementation. Apart from the schemes commenced in 2007-08, it is proposed to implement the following schemes/measures in 2008-09 :

- a multi-sectoral development plan for each of the 90 minority concentration districts will be drawn up at a cost of Rs. 3,780 crore. The allocation in 2008-09 will be Rs. 540 crore;
- a pre-matric scholarship scheme with an allocation of Rs. 80 crore next year;
- a scheme for modernising Madrassa education for which a provision of Rs.45.45 crore has been made in 2008-09;
- 256 branches of public sector banks have been opened this year until December 2007 in districts with substantial minority population. 288 more will be opened by March 2008 and many more in 2008-09; and
- continuing the exercise started this year, more candidates belonging to the minority communities will be recruited to the Central Para-Military Forces.

48. I also propose to provide Rs. 60 crore to enhance the corpus fund of the Maulana Azad Education Foundation.

Women and Children

49. I confess that policy makers often tend to forget that one-half of the population is constituted by women and they are entitled to an equal share—and an equal say—in all programmes and schemes. Gender Budgeting has gained wider acceptance and credibility. Four more ministries/departments have set up gender budgeting cells taking the total number to 54. Honourable Members will find in the Budget documents a statement embracing 33 demands for grants contributed by 27 ministries/departments and 5 Union Territories. According to the statement, Rs.11,460 crore has been provided for 100 per cent women-specific schemes and Rs.16,202 crore for schemes where at least 30 per cent is for womenspecific programmes.

50. We will score another 'first' this year. A statement on child related schemes is included in the budget documents and Honourable Members will be happy to note that the total expenditure on these schemes is of the order of Rs. 33,434 crore.

51. I propose to allocate Rs.7,200 crore in 2008-09 to the Ministry of Women and Child Development. This represents an increase of 24 per cent over the allocation in 2007-08.

Self Help Groups

52. The Life Insurance Corporation of India (LIC) runs the Janashree Bima Yojana and offers life and permanent disability cover to people in 44 categories. One of the categories is Self Help Groups, but only 35,000 SHGs have been covered so far. Considering the fact that there are over 30 lakh SHGs credit-linked to banks, I propose to single out this category for special attention. I propose to ask LIC to rapidly scale up the scheme and cover all women SHGs that are credit-linked to banks. Since one-half of the premium is subsidized through the Social Security Fund, I propose to contribute Rs.500 crore to the corpus of the fund with the assurance that annual contributions will be made as the scheme is scaled up. This scheme, together with the Rashtriya Swasthya Bima Yojana, will mark the beginning of a new deal for women by providing them life and health cover.

Supplement to GBS

53. Honourable Members will note that the allocations to various sectors and schemes are generous. I hasten to add that more can be done and more will be done subject, however, to one condition: the condition of performance. In the last Budget, I had announced a Plan 'B' and I was able to provide additional Plan funds of Rs. 8,365 crore in cash through two supplementaries - and a third one will follow shortly. The nub of the problem lies in implementation - and implementation mostly is in the hands of State Governments. This year too, I intend to mobilise additional resources to the tune of Rs.10,000 crore to be used for Plan capital expenditure. This money—under Plan 'B'—will be available to ministries/departments of the Central Government and to State Governments that achieve the physical and quality targets set under

different Plan schemes.

III. AGRICULTURE

54. I shall now return to the subject of agriculture.

55. I have already referred to the Rashtriya Krishi Vikas Yojana and the National Food Security Mission.

Agricultural Credit

56. Notwithstanding some shortcomings, the growth of agricultural credit has been impressive and for this I have to thank our scheduled commercial banks and Regional Rural Banks. Between them, they account for about 75-79 per cent of agricultural credit disbursed during any year. We will exceed the target set for 2007-08. For 2008-09, I propose to set a target of Rs. 280,000 crore.

57. Short-term crop loans will continue to be disbursed at 7 per cent per annum and I am making an initial provision of Rs. 1,600 crore for interest subvention in 2008-09.

Investment in Agriculture

58. What ails agriculture, among other things, is the fall in investment. However, there seems to be a turnaround. Gross Capital Formation (GCF) in agriculture as a proportion of GDP in the agriculture sector has improved from a low of 10.2 per cent in 2003-04 to 12.5 per cent in 2006-07. This, however, needs to be raised to 16 per cent during the Eleventh Plan to achieve the target growth rate of 4 per cent.

Water Resources

59. Government is investing heavily in the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) and the Rainfed Area Development Programme and in the management and augmentation of water resources. Under AIBP, 24 major and medium irrigation projects and 753 minor irrigation schemes will be completed in this financial year, creating additional irrigation potential of 500,000 hectare. The outlay for 2007-08 was Rs. 11,000 crore with a grant component of Rs. 3,580 crore. These are being increased in 2008-09, and the estimated outlay is Rs. 20,000 crore with a grant component of Rs. 5,550 crore.

60. The Rainfed Area Development Programme has been finalised and will be implemented in 2008-09 with an allocation of Rs. 348 crore. Priority will be given to those areas that have not been the beneficiaries of watershed development schemes.

61. The centrally sponsored scheme on micro irrigation launched in January 2006 has brought an area of 548,000 hectare under drip and sprinkler irrigation within two years. I propose to allocate Rs. 500 crore for the scheme in 2008-09 with a target of covering another 400,000 hectare.

62. Agreements have been signed with the World Bank by the Governments of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka under the project to repair, renovate and restore water bodies. The three agreements are for a total sum of US\$738 million that will benefit a command area of 900,000 hectare. I am confident that similar agreements will be signed soon between the World Bank and the Governments of Orissa, West Bengal and some other States.

Irrigation and Water Resources Finance Corporation

63. While these ongoing programmes will raise the level of investment in agriculture, I think that we need an ambitious scheme of a much larger proportion. Government is of the view that massive investments are required to be made in irrigation projects. Recently, Government has approved 14 projects that satisfy certain criteria as national projects and three of them alone would require Rs. 7,000 crore during the Eleventh Plan period. Having regard to the magnitude of the challenge, I propose to establish the Irrigation and Water Resources Finance Corporation (IWRFC) with an initial capital of Rs. 100 crore contributed by the Central Government. State Governments and other financial institutions will be invited to contribute to the equity. It is our intention to mobilise the very large resources that will be required to fund major and medium irrigation projects. I hope to be able to incorporate IWRFC as a company before March 31, 2008.

National Horticulture Mission

64. The National Horticulture Mission (NHM) now covers 340 districts in 18 States and two Union Territories. An area of 276,000 hectare has been brought under horticulture crops and an area of 56,000 hectare of old plantations has been rejuvenated. Special thrust is being given to the revival of crops such as coconut, cashew and pepper. NHM will be provided Rs. 1,100 crore in 2008-09.

65. 500 soil testing laboratories will be set up in the public and private sectors during the Eleventh Plan period with Government assistance of Rs. 30 lakh per laboratory. In addition, I propose to make a one-time allocation of Rs. 75 crore to the Ministry of Agriculture in order to provide one fully-fitted mobile soil testing laboratory each to 250 districts of the country before March 2009.

Plantation Crops

66. The Special Purpose Tea Fund set up last year for re-plantation and rejuvenation will be provided Rs. 40 crore in 2008-09. I propose to provide funds for similar support to other plantation crops such as cardamom (Rs. 10.68 crore), rubber (Rs. 19.41 crore) and coffee (Rs. 18 crore). A crop insurance scheme for tea, rubber, tobacco, chilli, ginger, turmeric, pepper and cardamom will be introduced next year.

67. In order to promote research on matters concerning the plantation sector, I propose to make a one-time grant of Rs. 5 crore to the Centre for Development Studies, Tiruvananthapuram. The Tocklai Experimental Station at Jorhat of the Tea Research Association will celebrate its centenary in 2010. It is in the process of upgrading its facilities and expanding its activities to cover other North Eastern States, North Bengal and Darjeeling. I propose to make a special centenary grant of Rs. 20 crore to the Tea Research Association.

68. The National Plant Protection Training Institute at Hyderabad will be converted and upgraded into an autonomous National Institute of Plant Health Management with budgetary support of Rs. 29.4 crore.

Crop Insurance

69. Pending a decision on an alternative crop insurance scheme that is acceptable to the farmers as well as viable to the insurer, the National Agriculture Insurance Scheme (NAIS) will be continued in its present form for Kharif and Rabi 2008-09. I propose to provide Rs. 644 crore for the scheme.

70. In addition, the Weather Based Crop Insurance Scheme that is being implemented as a pilot scheme in selected areas of five States will be continued. I intend to provide Rs. 50 crore for this purpose in 2008-09.

71. Government will continue to provide fertilisers to farmers at subsidized prices. Government is examining proposals to move to a nutrient based subsidy regime and alternative methods of delivering the subsidy.

Cooperative Credit Structure

72. The Prof. Vaidyanathan Committee's report on reviving the short-term cooperative credit structure is under implementation in 17 States. So far, a sum of Rs. 1,185 crore has been released by the Central Government to four States. I am happy to report that the Central Government and the State Governments have reached an agreement on the content of the package to implement the Prof. Vaidyanathan Committee's report on reviving the long-term cooperative credit structure. The cost of the package is estimated at Rs. 3,074 crore, of which the Central Government's share will be Rs. 2,642 crore or 86 per cent of the total burden.

Debt Waiver and Debt Relief

73. Sir, while I am confident that the schemes and measures that I have listed above will give a boost to the agriculture sector, the question that still looms large is what we should do about the indebtedness of farmers. Honourable members will recall that Government had appointed a Committee under Dr. R. Radhakrishna to examine all aspects of agricultural indebtedness. The Committee has since submitted its report and it is in the public domain. The Committee had made a number of recommendations but stopped short of recommending waiver of agricultural loans. However, Government is conscious of the dimensions of the problem and is sensitive to the difficulties of the farming community, especially the small and marginal farmers. Having carefully weighed the pros and cons of debt waiver and having taken into account the resource position, I place before this House a scheme of debt waiver and debt relief for farmers:

- (i) All agricultural loans disbursed by scheduled commercial banks, regional rural banks and cooperative credit institutions up to March 31, 2007 and overdue as on December 31, 2007 will be covered under the scheme.
- (ii) For marginal farmers (i.e., holding up to 1 hectare) and small farmers (1-2 hectare), there will be a complete waiver of all loans that were overdue on December 31, 2007 and which remained unpaid until February 29, 2008. In respect of other farmers, there will be a one time settlement (OTS) scheme for all loans that were overdue on December 31, 2007 and which remained unpaid until February 29, 2008. Under the OTS, a rebate of 25 per cent will be given against payment of the balance of 75 per cent.
- (iii) Agricultural loans were restructured and rescheduled by banks in 2004 and 2006 through special packages.

These rescheduled loans, and other loans rescheduled in the normal course as per RBI guidelines, will also be eligible either for a waiver or an OTS on the same pattern.

- (iv) The implementation of the debt waiver and debt relief scheme will be completed by June 30, 2008. Upon being granted debt waiver or signing an agreement for debt relief under the OTS, the farmer would be entitled to fresh agricultural loans from the banks in accordance with normal rules.
- (v) Government estimates that about three crore small and marginal farmers and about one crore other farmers will benefit from the scheme. The total value of overdue loans being waived is estimated at Rs.50,000 crore and the OTS relief on the overdue loans is estimated at Rs.10,000 crore.

I appeal to Honourable Members - as well as to the people of India - to give their unqualified support to the scheme and help Government implement this momentous decision.

IV. INVESTMENT, INFRASTRUCTURE, INDUSTRY AND TRADE

74. Since 2005-06, there has been an unmistakable boom in investment. Two indicators tell the story. The saving rate and the investment rate in 2003-04 were 29.8 per cent and 28.2 per cent, respectively. According to estimates made by the Economic Advisory Council to the Prime Minister, they will be 35.6 per cent and 36.3 per cent, respectively, by the end of 2007-08. The trend is reflected on the foreign investment side too. During the period April-December 2007-08, foreign direct investment amounted to US\$12.7 billion and foreign institutional investment to US\$18 billion. Our policy is to encourage all sources of investment, domestic and foreign, private and public.

75. In 2008-09, Government will provide Rs.16,436 crore as equity support and Rs. 3,003 crore as loans to Central Public Sector Enterprises (CPSEs). 44 CPSEs are listed today. It is the policy of the Government to list more CPSEs in order to unlock their true value and improve corporate governance.

Rural Infrastructure Development Fund

76. The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) is the main instrument to channelize bank funds for financing rural infrastructure, and it is quite popular among State Governments. Therefore, I propose to raise the corpus of RIDF XIV in 2008-09 to Rs.14,000 crore. I also propose to operate a separate window under RIDF-XIV for rural roads with a corpus of Rs 4,000 crore.

Manufacturing Sector

77. There has been some moderation in the index of production of the six crore infrastructure industries as well as in the overall index of industrial production for the period April-December 2007-08. The decline has been somewhat sharp in the case of consumer goods, especially consumer durables. The silver lining is that the growth in capital goods is still very high at 20.2 per cent, indicating that industry continues to make huge capital investments and has a positive outlook about the future. Manufacturing industries that have grown more slowly than the average include food products, cotton textiles, textile products including apparel, paper and transport equipment. Among the reasons for the moderation are a rise in interest rates and the appreciation of the Rupee. There are limits to monetary policy accommodation, especially when the need is to maintain price stability. However, some steps can be taken on the fiscal side and I shall, presently, place before the House some proposals in order to stimulate industrial growth. Our goal is to take the manufacturing growth rate to a double digit. This will also call for more reforms in the coal and electricity sectors as well as confronting oligopolistic tendencies in the cement and steel sectors.

Power

78. The Eleventh Plan target for additional power generation capacity is 78,577 MW which is more than the total capacity added in the previous three Plans. By end March 2008, we will achieve Commercial Operation Date (COD) on about 10,000 MW, marking the best first year in any Plan period. Government will redouble its efforts to ensure that the ambitious target for the Eleventh Plan is achieved.

79. The fourth Ultra Mega Power Project (UMPP) at Talaiya will be awarded shortly. It is possible to bring five more UMPPs in Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra, Orissa and Tamilnadu to the bidding stage provided the States extend the required support. I urge them to do so.

80. Government has approved the continuation of the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana during the Eleventh Plan period with a capital subsidy of Rs.28,000 crore. I propose to allocate Rs.5,500 crore in 2008-09 for the Yojana (including NER).

81. I propose to provide Rs.800 crore in 2008-09 for the Accelerated Power Development and Reforms Project. However, it is the poor state of transmission and distribution (T & D) that is a drag on the sector. Huge investments are required to be made in T & D, but linked to fundamental reforms. Hence, I propose to create a national fund for transmission and distribution reform. The details of the scheme will be worked out and announced very soon.

Roads

82. All phases of the National Highway Development Programme continue to make progress. The completion ratio in the Golden Quadrilateral is 96.48 per cent and in the North-South, East-West Corridor Project is 23.36 per cent. Special attention is being paid to SARDP-NE, a programme devised for the North Eastern region. 180 kms of roads were completed in 2007-08 and the target for 2008-09 is 300 kms. I propose to enhance the allocation for the NHDP from Rs.10,867 crore in 2007-08 to Rs.12,966 crore next year.

Oil and Gas

83. The 7th round of bidding under the New Exploration Licensing Policy (NELP) was launched in December 2007 and bids have been invited for 57 exploration blocks. It is estimated that the round will attract investment of the order of US\$3.5 billion to US\$8 billion for exploration and discovery.

Coal

84. 53 coal blocks with reserves of 13,842 million tonnes have been allotted during April-January 2007-08 to Government and private sector companies. A new Coal Distribution Policy was notified in October 2007. A coal regulator will be appointed.

Information Technology

85. Government's forward looking policy is driving the growth of Information Technology and Information Technology Enabled Services. I propose to enhance the allocation to the Department of Information Technology from Rs.1,500 crore in 2007-08 to Rs.1,680 crore in 2008-09. A scheme for establishing 100,000 broadband internet-enabled Common Service Centres in rural areas and a scheme for establishing State Wide Area Networks (SWAN) with Central assistance are under implementation. A new scheme for State Data Centres has also been approved. I propose to provide Rs.75 crore for the common service centres, Rs.450 crore for SWAN and Rs.275 crore for the State Data Centres.

Textiles

86. The two principal schemes of the Ministry of Textiles - the Scheme for Integrated Textile Parks (SITP) and the Technology Upgradation Fund (TUF)—will be continued in the Eleventh Plan period. All 30 integrated textile parks have been approved and 20 units in four parks have commenced production. I propose to maintain the provision for SITP at Rs. 450 crore in 2008-09. The provision for TUF will be increased from Rs.911 crore in the current year to Rs.1,090 crore in 2008-09.

87. The cluster approach to the development of the handloom sector has made rapid progress. 250 clusters are being developed. 443 yam banks have been established. By March 2008, over 17 lakh families of weavers will be covered under the health insurance scheme. I propose to increase the allocation to Rs. 340 crore in 2008-09.

88. In order to scale up both infrastructure and production, it is proposed to take up six centres for development as mega-clusters. Varanasi and Sibsagar will be taken up for handlooms, Bhiwandi and Erode for powerlooms, and Narsapur and Moradabad for handicrafts. Each mega-cluster will require about Rs.70 crore. I propose to start the process with an initial provision of Rs.100 crore in 2008-09.

Micro, Small and Medium Enterprises

89. Micro, small and medium enterprises will continue to receive support from the Government. I wish to remove certain wrong perceptions about the sector. In the four years ending 2006-07, for which figures are available, there has been a secular rise in the number of registered units, the number of unregistered units, production, employment and exports. In order to give a fillip to the sector, I propose to create a risk capital fund in the Small Industries and Development Bank of India (SIDBI). As on January 31, 2008, the Credit Guarantee Trust with SIDBI had extended guarantees to 89,129 units for an amount of Rs. 2,479 crore. SIDBI will reduce the guarantee fee from 1.5 per cent to 1 per cent and the annual service fee from 0.75 per cent to 0.5 per cent for loans up to Rs. 5 lakh.

Foreign Trade

90. Merchandise exports have come under some pressure due to the appreciation of the Rupee and may fall just short of the target of US\$ 160 billion, although the growth rate was strong at 21.8 per cent during April-December 2007-08.

Relief was given to exporters in three tranches amounting to over Rs.8,000 crore. I may note that the interest cost of sterilization through market stabilization bonds (MSS), estimated at Rs.8,351 crore for the whole year is, in a sense, subsidy to the export sector. Government is sensitive to the needs of the export sector and will continue to respond sympathetically as the situation demands.

V. FINANCIAL SECTOR

91. Government's policy of a careful and calibrated opening of the financial sector has proved successful. We shall continue to take measured steps.

92. The final report of the Committee on Financial Inclusion has been received. To begin with, I propose to accept two recommendations:

- to advise commercial banks, including RRBs, to add at least 250 rural household accounts every year at each of their rural and semi-urban branches; and
- to allow individuals such as retired bank officers, ex-servicemen etc. to be appointed as business facilitator or business correspondent or credit counsellor.

93. Banks will be encouraged to embrace the concept of Total Financial Inclusion. Government will request all scheduled commercial banks to follow the example set by some public sector banks and meet the entire credit requirements of SHG members, namely, (a) income generation activities; (b) social needs like housing, education, marriage etc.; and (c) debt swapping.

NABARD, SIDBI and NHB

94. Financial inclusion can be taken forward by expanding the reach of NABARD, SIDBI and NHB. Hence, in order to increase the resource base of these three banks, I propose to tap into the resources of scheduled commercial banks to the extent that they fall short of their obligation to lend to the priority sector. Accordingly, it is proposed to create the following funds:

- (i) a fund of Rs.5,000 crore in NABARD to enhance its refinance operations to short-term cooperative credit institutions;
- (ii) two funds of Rs. 2,000 crore each in SIDBI—one for risk capital financing and the other for enhancing refinance capability to the MSME sector; and
- (iii) a fund of Rs.1,200 crore in NHB to enhance its refinance operations in the rural housing sector.

Each of these funds will be governed by the general guidelines that are now applicable to RIDF with some modifications.

95. Last year, I enhanced the limit of the loan that could be extended under the Differential Rate of Interest (DRI) scheme to the weaker sections of the community engaged in gainful occupations. However, I did not enhance the eligibility criteria which still stand at levels fixed in 1986. This needs to be corrected. Hence, I propose to fix the borrower's eligibility criteria as annual family income of Rs. 18,000 in rural areas and Rs. 24,000 in urban areas.

Capital Markets

96. In my Budget Speech of 2006, I had informed the House that, on the basis of the R.H. Patil Committee Report, we shall take steps to create an exchange-traded market for corporate bonds. Both Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange have created platforms for trading in corporate bonds.

97. I intend to move forward by taking some more measures to expand the market for corporate bonds. Hence, I propose to :

- take measures to develop the bond, currency and derivatives markets that will include launching exchange-traded currency and interest rate futures and developing a transparent credit derivatives market with appropriate safeguards;
- enhance the tradability of domestic convertible bonds by putting in place a mechanism that will enable investors to separate the embedded equity option from the convertible bond and trade it separately; and
- encourage the development of a market-based system for classifying financial instruments based on their complexity and implicit risks.

98. The fear of the Permanent Account Number (PAN) has virtually disappeared. PAN is now the sole identification number for all participants in the securities market. I propose to extend the requirement of PAN to all transactions in the financial market subject, however, to suitable threshold exemption limits.

99. Our stock exchanges provide national electronic trading platforms for securities transactions. Yet, we do not

have a seamless national market for securities because of differences among States on the scope and applicability of rates of stamp duty. Hence, I propose to request the Empowered Committee of State Finance Ministers to work with the Central Government to create a truly pan Indian market for securities that will expand the market base and enhance the revenues of the State Governments.

VI. OTHER PROPOSALS

100. India is poised to reap a 'demographic dividend' because the size of its working age population will increase from about 77.5 crore in 2008 to a likely peak of 95 crore in 2026. The 'dividend' can prove illusory if the workforce does not acquire the skills to support a knowledge and technology driven economy.

Skill Development Mission

101. Today, skill development programmes are diffused and administered by a number of ministries/departments. I have no intention of interfering with these sector-specific programmes. However, there is a compelling need to launch a world-class skill development programme, in mission mode, that will address the challenge of imparting the skills required by a growing economy. Both the structure and the leadership of the mission must be such that the programme can be scaled up quickly to cover the whole country. Hence, I propose to establish a non-profit corporation and entrust the mission to that corporation. It is my intention to garner about Rs. 15,000 crore as capital from Governments, the public and private sector, and bilateral and multilateral sources. I shall begin by putting Rs. 1,000 crore as Government's equity in the proposed non-profit corporation.

Industrial Training Institutes

102. The upgradation of ITIs is proceeding apace. Under the World Bank assisted scheme, 238 ITIs are undergoing upgradation. Under the PPP scheme, 309 ITIs in 29 States have been identified with corresponding industry partners and agreements have been signed in 244 cases. In anticipation of upgrading 300 more ITIs in 2008-09, I have set apart Rs. 750 crore.

Sainik Schools

103. I am concerned by the rate of attrition in the defence forces, especially at the officer level. Sainik Schools have played a unique role as recruiting and training ground of future leaders of the defence forces. I propose to make an allocation of Rs. 44 crore at the rate of Rs. 2 crore each to the 22 Sainik Schools for immediate improvement of infrastructure including classrooms, laboratories, libraries and facilities for physical education.

Public Distribution System

104. A sum of Rs. 32,667 crore is being provided next year for food subsidy under the Public Distribution System (PDS) and other welfare programmes. Strengthening the PDS would mean adequate supplies, reasonable subsidies and efficient delivery of the subsidized food. An idea that has been growing is to deliver subsidies to the target group through smart cards. Finally, I have found two willing partners—the State of Haryana and the Union Territory of Chandigarh. They will introduce, on a pilot basis, a smart card based delivery system to deliver foodgrains under the PDS in Haryana and Chandigarh, respectively. I thank the Chief Minister of Haryana and the Administrator of Chandigarh and promise them full support and cooperation in making a success of the pilot scheme.

Unorganised Sector Workers

105. The Unorganised Sector Workers' Social Security Bill, 2007 is before Parliament. In anticipation of the Bill being made into law, Government has introduced three schemes that are designed to provide social security to workers in the unorganised sector in a phased manner. These are :

- the Aam Admi Bima Yojana that will provide insurance cover to poor households. I am happy to announce that, in the first year of the Yojana, LIC will cover one crore landless households by September 30, 2008. I have already placed Rs. 1,500 crore with LIC. In order to cover another one crore poor households in the second year, I propose to place an additional sum of Rs. 1,000 crore with LIC in 2008-09;
- the Rashtriya Swasthya Bima Yojana that will be implemented with effect from April 1, 2008; and
- the Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme that was enlarged with effect from November 19, 2007 to include all persons over 65 years falling under the BPL category. Consequently, the coverage has expanded from 87 lakh to 157 lakh beneficiaries. I propose to allocate Rs. 3,443 crore in 2008-09 as against Rs. 2,392 crore in 2007-08.

Housing for the Poor

106. Housing for the poor is one of the six elements of Bharat Nirman and is implemented through the Indira Awas Yojana (IAY). Against a target of 60 lakh houses, 41.13 lakh houses have been constructed up to December 2007 and the

cumulative number will be 51.77 lakh houses by end March 2008. Reflecting the higher cost of construction, I propose to enhance the subsidy per unit in respect of new houses sanctioned after April 1, 2008 from Rs. 25,000 to Rs. 35,000 in plain areas and from Rs. 27,500 to Rs. 38,500 in hill/difficult areas. The subsidy for up gradation of houses will be increased from Rs. 12,500 per unit to Rs. 15,000. A beneficiary will still need own funds to complete the house. Public sector banks will be advised to include IAY houses under the differential rate of interest (DRI) scheme and lend up to Rs. 20,000 per unit at an interest rate of 4 per cent.

Defence

107. I propose to increase the allocation for Defence by 10 per cent from Rs. 96,000 crore to Rs. 105,600 crore. I have assured the Raksha Mantri that any further amount needed for the Defence Forces, especially for capital expenditure, will be provided.

Backward Regions Grant Fund

108. The Backward Regions Grant Fund was given Rs. 5,800 crore in the current year. Having regard to the pace of expenditure, I propose to keep the allocation for the next year at the same level. I may add that nearly 45 per cent of the amount is likely to be allocated to the States of Bihar, Orissa and Uttar Pradesh.

Climate Change

109. In the Budget Speech last year I had announced the decision of the Government to appoint an expert committee to study the impact of climate change on India and identify the measures that we may have to take in the future. Work is in progress. Even while adhering to the principle of "common but differentiated responsibility" we can—and we must—do a number of things in our self-interest. We can promote clean technology products; we can review fuel emission and efficiency regulations; we can replace wood by solar as the fuel of common use; we can encourage the use of gas which is the most benign hydrocarbon; we can set up a trading platform for carbon emissions; we can build sustainable greenfield cities; and we can do more. In order to explore and implement these and other ideas, Government proposes to establish a permanent institutional mechanism that will play a development and coordination role. Details of the institutional mechanism will be announced shortly.

Sixth Central Pay Commission

110. I have been informed that the Sixth Central Pay Commission will submit its report by March 31, 2008. I am confident that the report will meet the legitimate expectations of Government employees.

Commonwealth Games

111. The Commonwealth Games are only 947 days away. As promised, we shall provide Rs. 624 crore in 2008-09. I would urge the authorities concerned to adhere to the strict timelines and the quality standards.

Institutions of Excellence

112. For the fourth year in succession, I propose to make a special grant of Rs. 100 crore each to three institutions of excellence. The awards for 2008-09 go to : (i) Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth, Rahuri, Maharashtra; (ii) University of Mysore, Mysore; and (iii) Delhi University, Delhi.

India's Soft Power

113. India's music, literature, dance, art, cuisine and especially films are attracting huge interest around the world. This is the 'soft power' of India, and it must be projected in a sophisticated and subtle manner. I propose to provide Rs. 75 crore to the Indian Council of Cultural Relations to design and implement a programme to achieve this objective.

Tiger Protection

114. The number 1,411 should ring the alarm bells. That is the number of tigers in India. The tiger is under grave threat. In order to redouble our effort to protect the tiger, I propose to make a one time grant of Rs. 50 crore to the National Tiger Conservation Authority. The bulk of the grant will be used to raise, arm and deploy a special Tiger Protection Force.

Monitoring and Evaluation

115. Robust economic growth has thrown up many new challenges, among them the need to put in place effective monitoring, evaluation and accounting systems for the large sums of money that are disbursed by the Central Government to State Governments, district level agencies and other implementing agencies. I think we do not pay enough attention to

outcomes as we do to outlays; or to physical targets as we do to financial targets; or to quality as we do to quantity. Government therefore proposes to put in place a Central Plan Schemes Monitoring System (CPSMS) that will be implemented as a Plan scheme of the Planning Commission. A comprehensive Decision Support System and Management Information System will also be established. The intended outcome is to generate and monitor scheme-wise and State-wise releases for about 1,000 Central Plan and centrally sponsored schemes in 2008-09.

116. Government also intends to strengthen evaluation. Some ministries have started concurrent evaluation. This needs to be supplemented by independent evaluations conducted by research institutions. The Planning Commission will authorise such evaluations of the major schemes and complete the task by the time of the mid-term review of the Eleventh Plan.

VII. BUDGET ESTIMATES

117. I shall now turn to the Budget Estimates for 2008-09.

118. The estimate of Plan Expenditure is placed at Rs. 243,386 crore. As a proportion of total expenditure, it will be 32.4 per cent.

119. Non-Plan Expenditure is estimated at Rs. 507,498 crore.

Revenue Deficit and Fiscal Deficit

120. It is widely acknowledged that the fiscal position of the country has improved tremendously. I am happy to report that the revenue deficit for the current year will be 1.4 per cent (against a BE of 1.5 per cent) and the fiscal deficit will be 3.1 per cent (against a BE of 3.3 per cent).

121. Further progress will be made in 2008-09. The revenue receipts of the Central Government for 2008-09 are projected at Rs. 602,935 crore and the revenue expenditure at Rs. 658,119 crore. Consequently, the revenue deficit is estimated at Rs. 55,184 crore, which amounts to 1.0 per cent of GDP. The fiscal deficit is estimated at Rs. 133,287 crore which is 2.5 per cent of GDP. Honourable Members will note that not only will I achieve the target for fiscal deficit under the FRBM Act, I have also left for myself some headroom. In the case of revenue deficit, I will meet the target of annual reduction of 0.5 per cent. However, because of the conscious shift in expenditure in favour of health, education and the social sector, we may need one more year to eliminate the revenue deficit. In my view, this is an entirely acceptable deferment.

Revisiting the Roadmap for Fiscal Adjustment

122. I acknowledge that significant liabilities of the Government on account of oil, food and fertilizer bonds are currently below the line. This accounting arrangement is consistent with past practice. Nevertheless, our fiscal and revenue deficits are understated to that extent. There is a need to bring these liabilities into our fiscal accounting. As a first step, I have shown these liabilities clearly in 'Budget at a Glance'. After the obligations on account of the Sixth Central Pay Commission become clear, I intend to request the Thirteenth Finance Commission to revisit the roadmap for fiscal adjustment and suggest a suitably revised roadmap.

PART - B

VIII. TAX PROPOSALS

123. Mr. Speaker, I shall now present my tax proposals.

124. Many people are surprised by the buoyancy in tax revenues, especially in direct taxes. I am not I have always maintained that moderate and stable tax rates coupled with a tax administration that shows no fear or favour will bring high revenues to the exchequer.

125. The UPA Government inherited a tax to GDP ratio of 9.2 per cent in 2003-04. At the end of 2007-08, that ratio would have risen to 12.5 per cent.

126. High growth rates have helped. Changes in attitude have also helped. Above all, information systems and technology have helped most. And, if I may add in a lighter vein, having a lucky Finance Minister may have also helped ! We are on course to achieve the Budget Estimates of indirect taxes and exceed the Budget Estimates of direct taxes. I take this opportunity to thank all tax payers and I promise them an efficient and tax payer-friendly administration.

Indirect Taxes

127. I shall begin with customs duties.

128. The peak rate for non-agricultural products was 20 per cent in January 2004 and now stands at 10 per cent. The collection rate is the closest approximation to the level of protection to domestic industry, and that rate for all imports stood at 10 per cent in 2006-07. Since April 2007, the Rupee has appreciated against the Dollar by 9.8 per cent. Consequently, the case for reducing the peak rate at this stage is very weak. Hence, I propose to make no change in the peak rate of customs duty.

129. However, I find that in some cases it is necessary to reduce the customs duty in order to provide a fillip to that industry or to promote value addition or to remove inversion or any other anomaly. I shall refer to a few such cases.

130. I propose to reduce the customs duty on Project Imports from 7.5 per cent to 5 per cent. However, I also propose to impose the 4 per cent special CVD on a few specified projects in the power sector.

131. In order to improve the supply of raw material, I propose to reduce the duty on steel melting scrap and aluminium scrap from 5 per cent to nil.

132. On certain specified life saving drugs and on the bulk drugs used for the manufacture of such drugs, I propose to reduce the customs duty from 10 per cent to 5 per cent as well as to totally exempt them from excise duty or countervailing duty.

133. In order to reduce the cost of manufacture of cattle and poultry feeds, I propose to reduce the duty on vitamin premixes and mineral mixtures from 30 per cent to 20 per cent and on phosphoric acid from 7.5 per cent to 5 per cent.

134. The duty on bactofuges will be reduced from 7.5 per cent to nil. This will increase the shelf life of milk and benefit the dairy industry.

135. I propose to fully exempt from duty specified parts of set top boxes and specified raw materials for use in the IT/electronic hardware industry.

136. To establish parity between devices used in the information/ communication sector and the entertainment sector, I propose to reduce the duty on convergence products from 10 per cent to 5 per cent.

137. To provide a fillip to the manufacture of sports goods, I propose to reduce the duty on specified machinery from 7.5 per cent to 5 per cent. I also propose to exempt from duty specified raw materials for sports goods.

138. The gem and jewellery industry has responded well to the duty reductions made last year. In order to encourage value addition and exports, I propose to exempt from duty rough cubic zirconia and to reduce the duty on polished cubic zirconia from 10 per cent to 5 per cent. Similarly, the duty on rough coral will be reduced from 10 per cent to 5 per cent.

139. To facilitate training of helicopter pilots, I propose to remove the duty on helicopter simulators.

140. In order to support domestic fertiliser production, I propose to reduce the customs duty on crude and unrefined sulphur from 5 per cent to 2 per cent.

141. Thanks to a complex regime of export benefits and duty exemptions, naphtha is exported from refineries and naphtha is imported by manufacturers of polymers, leading to price distortions and revenue losses. I propose to correct the situation by withdrawing the duty exemption on naphtha for use in the manufacture of polymers and subject it to the normal rate of 5 per cent. However, naphtha imported for the production of fertilisers will continue to be exempt from import duty.

142. Finally in order to conserve chrome ore and make it available for value added manufacture in India, I propose to increase the export duty from Rs.2,000 per metric tonne to Rs.3,000 per metric tonne.

143. I shall allow deal with excise duties.

144. The manufacturing sector is the backbone of any economy. It is consumption that drives production and it is production that drives investment. Having carefully studied current trends of production and consumption, I believe there is a need to give a stimulus to the manufacturing sector. Hence, I propose to reduce the general CENV AT rate on all goods from 16 per cent to 14 per cent.

145. I have looked at specific sectors where growth is flagging. These sectors are important because they are growth and employment drivers. Some of them also have large externalities. Therefore, I propose to:

- reduce the excise duty on all goods produced in the pharmaceutical sector from 16 per cent to 8 per cent;

- reduce the excise duty on buses and their chassis from 16 per cent to 12 per cent;
- reduce the excise duty on small cars from 16 per cent to 12 per cent and on hybrid cars from 24 per cent to the general revised rate of 14 per cent;
- reduce the excise duty on two wheelers and three wheelers from 16 per cent to 12 per cent; and
- reduce the excise duty on paper, paper board and articles made therefrom manufactured out of non-conventional raw materials by units not having an attached bamboo/wood pulp making plant from 12 per cent to 8 per cent with a further reduction on clearances up to 3,500 MT from 8 per cent to nil. Furthermore, excise duty on certain varieties of writing, printing and packing paper will be reduced from 12 per cent to 8 per cent.

146. There are a number of products which are goods of mass consumption. There is also the need to have tax parity on similar goods. Taking into account requests from a number of industries, I propose to reduce the excise duty from 16 per cent to nil on a few items including composting machines, wireless data cards, packaged coconut water, tea and coffee mixes, and puffed rice.

147. Further, I propose to reduce the excise duty from 16 per cent to 8 per cent on a few items including water purification devices, veneers and flush doors, sterile dressing pads, specified packaging material, and breakfast cereals.

148. I propose to totally exempt from excise duty the anti AIDS drug, Atazanavir, as well as bulk drugs for its manufacture.

149. To further encourage cold chain facilities, I propose to exempt from excise duty, on end-use basis, refrigeration equipment (consisting of compressor, condenser units, evaporator etc.) above 2 TR (tonne refrigeration) utilising power of 50 KW and above.

150. I propose to bring parity in the excise duty rates on bulk cement and packaged cement. Accordingly, bulk cement will now attract excise duty of Rs. 400 per Metric Tonne or 14 per cent ad valorem, whichever is higher. Cement clinkers will be liable to excise duty of Rs. 450 per Metric Tonne.

151. Similarly, I propose to increase the excise duty on packaged software from 8 per cent to 12 per cent to bring it on par with customised software which will attract a service tax of 12 per cent.

152. Non-filter cigarettes are more toxic than filter cigarettes, yet they enjoy a favourable tax regime, which is iniquitous. I propose to tax both filter and nonfilter cigarettes on par by applying - as Honourable Members may have guessed - the higher rates.

153. In order to remove a source of misinformation, I propose to abolish the ad valorem part of the excise duty on unbranded petrol and unbranded diesel and replace the same by an equivalent specific duty of Rs. 1.35 per litre. Henceforth, there will be only a specific duty of Rs. 14.35 per litre on unbranded petrol and Rs. 4.60 per litre on unbranded diesel. There will be no impact on retail prices.

154. An excise duty of 1 per cent called NCCD is now imposed on polyester filament yarn, which is the only yarn suffering this excise duty. I propose to remove that duty and shift the levy to cellular mobile phones.

155. Finally, I turn to my proposals on service tax.

156. 55 per cent of the GDP is contributed by the services sector, which is a growing sector that must contribute its legitimate share to the exchequer. I propose to bring under the service tax net four services. They are:

- (i) asset management service provided under DUP, to bring it on par with asset management service provided under mutual funds;
- (ii) services provided by stock/commodity exchanges and clearing houses;
- (iii) right to use goods, in cases where VAT is not payable; and
- (iv) customised software, to bring it on par with packaged software and other IT services

157. I also propose to remove unwarranted doubts raised in respect of certain services and clarify that they are liable to service tax. These include money changers, persons running games of chance, and tour operators using contract carriage vehicles.

158. There are some miscellaneous changes but I do not wish to burden the House with the same.

159. Finally, I am happy to announce that the threshold limit of exemption for small service providers will be increased from Rs. 8 lakhs per year to Rs.10 lakh per year. As a result, about 65,000 small service providers will go out of the tax net.

Direct Taxes

160. I shall now deal with direct taxes.

161. I recall the Budget Speech of 1997. I believe that boldness pays. I also believe that trust will beget trust, moderation will beget revenues and fairness will beget compliance. Income tax payers have made out a persuasive case for some relief. Accordingly, I propose to make some changes in the slabs for personal income tax. I propose to increase the threshold limit of exemption :

- in the case of all assessees, from Rs.110,000 to Rs.150,000, thus giving every assessee a relief at a minimum of Rs. 4,000. Consequently, the four slabs and rates will be as follows :

Up to Rs.150,000	NIL
Rs. 150,001 to Rs.300,000	10 per cent
Rs. 300,001 to Rs.500,000	20 per cent
Rs.500,001 and above	30 per cent
- in the case of a woman assessee, from Rs.145,000 to Rs.180,000; in the case of a senior citizen, from Rs.195,000 to Rs.225,000.

162. I do not propose to make any change in the corporate income tax rates.

163. No change is proposed in the rate of surcharge.

164. I propose to add the Senior Citizens Savings Scheme 2004 and the Post Office Time Deposit Account to the basket of saving instruments under Section 80C of the Income Tax Act.

165. I propose to allow an additional deduction of Rs.15,000 under Section 80D to an individual who pays medical insurance premium for his/her parent or parents.

166. The Reverse Mortgage Scheme was notified by the National Housing Bank in the current financial year. In order to clarify the tax issues arising out of the scheme, I propose to amend the Income Tax Act to provide that :

- (i) reverse mortgage would not amount to "transfer"; and
- (ii) the stream of revenue received by the senior citizen would not be "income";

167. Agricultural income is exempt from income tax. However, courts have ruled that growing saplings or seedlings on land is agriculture but growing them in pots is not agriculture. This does not seem fair. Hence, I propose to exempt from tax income arising from saplings or seedlings grown in a nursery.

168. Companies engaged in certain businesses are allowed a weighted deduction of 150 per cent on any expenditure on in-house scientific research. I propose to add the business of production of seeds and manufacture of agricultural implements to this list.

169. In order to promote outsourcing of research, I propose to allow a weighted deduction of 125 per cent on any payment made to companies engaged in research and development.

170. I propose to extend the benefit of amortisation of certain preliminary expenses under Section 35D to assesseees in the services sector.

171. To supplement measures that I announced earlier in respect of the corporate debt market, I propose to exempt from TDS corporate debt instruments issued in demat form and listed on recognised stock exchanges.

172. I propose to make some changes in the provisions of law pertaining to Fringe Benefit Tax (FBT) that will give some relief to corporates and firms. Creche facilities, sponsorship of an employee-sportsperson, organising sports events for employees, and guest houses will be excluded from the purview of FBT.

173. At present, a domestic company is liable to pay Dividend Distribution Tax (DDT). As a result, the distributed dividend is sometimes taxed twice in the hands of a subsidiary company and its parent company, causing hardship. In order to remove the hardship, I propose to allow a parent company to set off the dividend received from its subsidiary company against dividend distributed by the parent company, provided that the dividend received has suffered DDT and the parent company is not a subsidiary of another company.

174. I propose to insert a new sub-section (11C) in Section 80-IG to grant a five year tax holiday to encourage hospitals to be set up anywhere in India, except certain specified urban agglomerations, and especially in tier-2 and tier-3 towns in order to serve the rural hinterland. This window will be open for the period April 1, 2008 to March 31, 2013, during which the hospital must commence operations.

175. Having regard to the significant rise in tourist arrivals, especially for cultural tourism, I propose to grant a five year holiday from income tax to two, three or four star hotels that are established in specified districts which have UNESCO-declared 'World Heritage Sites'. The hotel should be constructed and start functioning during the period April 1, 2008 to March 31, 2013.

176. I am happy to announce that the Coir Board will be included in Section 10(29A) and exempt from income tax.

177. Dividends that are distributed attract a tax of 15 per cent. Short term capital gains attract a tax of 10 per cent under Section 111A. There is merit in equating the rates and hence I propose to increase the rate of tax on short term capital gains under Section 111A and Section 115AD to 15 per cent. This will also encourage investors to stay invested for a longer term.

178. At present, Securities Transaction Tax (STT) paid is allowed as a rebate against tax liability. Further, STT on options is levied on the aggregate of the strike price and the option premium and is borne by the seller. I propose to make some changes. Henceforth, STT paid will be treated like any other deductible expenditure against business income. Further, the levy of STT, in the case of options, will be only on the option premium where the option is not exercised, and the liability will be on the seller. In a case where the option is exercised, the levy will be on the settlement price and the liability will be on the buyer. There will be no change in the present rates.

179. Transactions in commodity futures have come of age. Hence, I propose to introduce the Commodities Transaction Tax (CTT) on the same lines as STT on options and futures.

180. "Charitable purpose" includes relief of the poor, education medical relief and any other object of general public utility. These activities are tax exempt, as they should be. However, some entities carrying on regular trade, commerce or business or providing services in relation to any trade, commerce or business and earning incomes have sought to claim that their purposes would also fall under "charitable purpose". Obviously, this was not the intention of Parliament and, hence, I propose to amend the law to exclude the aforesaid cases. Genuine charitable organisations will not in any way be affected.

181. The Banking Cash Transaction Tax (BCTT) has served a very useful purpose in enlarging the information system of the Income Tax Department. Since the information is also being gathered through other instruments introduced in the last few years, I propose to withdraw this tax with effect from April 1, 2009.

182. My tax proposals on direct taxes are revenue neutral. On the indirect taxes side, the proposals are estimated to result in a loss of Rs.5,900 crore.

CST and a Roadmap towards GST

183. Following an agreement between the Central Government and the State Governments, the rate of Central Sales Tax was reduced from 4 per cent to 3 per cent in this financial year. It is now proposed to reduce the rate to 2 per cent from April 1, 2008. Consultations are underway on the compensation for losses, if any, and once agreement is reached the new rate will be notified. I am also happy to report that there is considerable progress in preparing a roadmap for introducing the Goods and Services Tax with effect from April 1, 2010.

IX. CONCLUSION

184. Mr. Speaker, Sir, once upon a time India, together with China, accounted for 50 per cent of the world's output. We must regain our position and it is within our capacity to do so.

185. Our work in Government is, every day and every hour, a discovery of the path to reach our goals: full employment, abolition of poverty and elimination of inequality. "These goals can only be achieved by a considerable increase in national income and our economic policy must, therefore, aim at plenty and equitable distribution. We must produce wealth, and then divide it equitably. How can we have a welfare state without wealth?" Those are not my words; they were uttered in 1955 by Pandit Jawaharlal Nehru. Although Jawaharlal Nehru did not use the phrase inclusive growth, he actually spelt out the conditions for inclusive growth.

186. Those words will guide the UPA Government. As always, I turned to my muse, Saint Tiruvalluvar, for guidance and reassurance. 2000 years ago he set the benchmark for good governance in the following immortal words :

"Kodai Ali Sengol Kudi Ombal Nangum

Udaiyanam Vendharkku Oli"

[Generous grants, compassion, righteous rule

and succour to the downtrodden

Are the hallmarks of good governance]

We have tried to remain true to this philosophy. The four years to 2007-08 have been the best years so far but, may I say with humility, that the best is yet to come.

187. Sir, with these words I commend the Budget to the House.

L. M. VAS, Addl. Secy. (Budget)